नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 267
दि. 30.06.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर युद्ध जैसे हालात, पाकिस्तानी हवाई हमलों में 36 नागरिकों की मौत; दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर

काबुल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से जारी सीमा तनाव अब एक बार फिर हिंसक टकराव में बदलता दिखाई दे रहा है। रविवार देर रात पाकिस्तानी सेना द्वारा अफगानिस्तान के विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में किए गए हवाई और सैन्य हमलों में कम से कम 36 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 160 से अधिक लोग घायल हो गए। मरने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और ग्रामीण शामिल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद दोनों देशों के संबंधों में नया तनाव पैदा हो गया है। पाकिस्तान ने इन हमलों को आतंकवाद के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई बताया है, जबकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन, कायरतापूर्ण आक्रामकता और निर्दोष नागरिकों पर बर्बर हमला करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की है।

अफगान अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने सबसे भीषण हमला पक्तिया प्रांत के चमकनी जिले में किया। तालिबान सरकार के उप-प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने बताया कि एक रिहायशी मकान को निशाना बनाए जाने से एक बुजुर्ग और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के कई अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद जब आसपास के ग्रामीण घायलों को बचाने और मलबे से लोगों को निकालने पहुंचे तो उसी क्षेत्र पर दोबारा हवाई हमला किया गया। इस दूसरे हमले में 28 ग्रामीणों की मौत हो गई और 158 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार, घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

अफगान प्रशासन ने बताया कि पक्तिका प्रांत के गियान जिले में भी एक गांव के रिहायशी मकान पर हवाई हमला किया गया, जिसमें छह लोगों की जान चली गई। मृतकों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुनार प्रांत में भी एक आम नागरिक के घर को निशाना बनाया गया। हालांकि वहां किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन मकान को भारी नुकसान पहुंचा है। अफगान अधिकारियों का आरोप है कि इन हमलों में सैन्य ठिकानों के बजाय नागरिक आबादी को नुकसान पहुंचा है, जिससे बड़ी मानवीय त्रासदी पैदा हुई है। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार ने इस

कार्रवाई को पूरी तरह आतंकवाद विरोधी अभियान बताया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने कहा कि रविवार देर रात पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अफगान सीमा के निकट जमीनी अभियान और हवाई कार्रवाई के दौरान आतंकवादियों के कई ठिकानों को निशाना बनाया। उनके अनुसार इस अभियान में 29 आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान का दावा है कि हाल के महीनों में देश के भीतर सुरक्षा बलों पर लगातार बढ़ रहे आतंकी हमलों के बाद यह कार्रवाई आवश्यक हो गई थी और इसका उद्देश्य केवल आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना था, न कि आम नागरिकों को निशाना बनाना।

पाकिस्तान में हाल के वर्षों में पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस्लामाबाद लगातार आरोप लगाता रहा है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और उससे जुड़े अन्य आतंकी संगठन अफगानिस्तान की सीमा के भीतर सुरक्षित ठिकानों से पाकिस्तान के खिलाफ हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि उसकी नवीनतम सैन्य कार्रवाई भी हाल ही में कराची स्थित पाकिस्तान रेंजर्स के क्षेत्रीय मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई है।

कराची में हुए उस हमले में तीन पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में तीन हमलावरों को मार गिराया, जबकि एक घायल हमलावर को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के अनुसार गिरफ्तार हमलावर अफगान नागरिक है। इस हमले की जिम्मेदारी जमात-उल-अहरार नामक संगठन ने ली है, जिसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का अलग हुआ गुट माना जाता है। पाकिस्तान का आरोप है कि सीमा पार मौजूद आतंकी नेटवर्क लगातार उसकी आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं और इसी कारण सीमापार अभियान चलाना पड़ा।

हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के इन दावों को स्वीकार नहीं किया है। काबुल का कहना है कि यदि किसी सुरक्षा संबंधी चिंता पर चर्चा करनी थी तो उसके लिए कूटनीतिक और द्विपक्षीय माध्यम उपलब्ध थे, लेकिन नागरिक क्षेत्रों पर हवाई हमला किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। तालिबान प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी इस घटना का संज्ञान लेने की अपील की है और कहा है कि निर्दोष नागरिकों की मौत क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना दोनों पड़ोसी देशों के बीच पहले से मौजूद अविश्वास को और गहरा कर सकती है। पाकिस्तान लंबे समय से सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को लेकर चिंता जताता रहा है, जबकि अफगानिस्तान बार-बार अपनी संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगाता रहा है। ऐसे में यह ताजा सैन्य कार्रवाई केवल सीमावर्ती संघर्ष नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के इस संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के लिए नई चुनौती बनती दिखाई दे रही है। अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय की निगाह इस बात पर टिकी है कि दोनों देश इस तनाव को कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से कम करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं या सीमा पर हालात और अधिक गंभीर रूप ले लेते हैं।

तृणमूल के 440 करोड़ के फंड पर सियासी संग्राम, हाईकोर्ट पहुंचा विवाद; पुलिस, बैंक और राज्य सरकार को नोटिस

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हुआ तृणमूल कांग्रेस का आंतरिक सत्ता संघर्ष अब पार्टी के खजाने तक पहुंच गया है। पार्टी के तीन बैंक खातों में जमा लगभग 440 करोड़ रुपये के संचालन और स्वामित्व को लेकर छिड़ा विवाद अब अदालत की चौखट पर पहुंच गया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पुलिस की कार्रवाई को चुनौती दी है और मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है। दूसरी ओर, पार्टी के भीतर नेतृत्व का दावा करने वाला दूसरा गुट भी इन खातों पर अपना अधिकार जता रहा है। इस विवाद ने न केवल तृणमूल कांग्रेस के संगठनात्मक संकट को उजागर किया है, बल्कि पार्टी के वित्तीय नियंत्रण को लेकर भी गंभीर कानूनी और राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं।

सोमवार को इस मामले का उल्लेख न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अदालत में किया गया। ममता बनर्जी गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। उन्होंने दलील दी कि पार्टी के बैंक खातों पर रोक लगने से संगठनात्मक और प्रशासनिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं,

इसलिए मामले की शीघ्र सुनवाई आवश्यक है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी अंतरिम राहत पर विचार करने से पहले सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करना आवश्यक है। न्यायालय ने पुलिस, संबंधित बैंक और राज्य सरकार को नोटिस भेजने का निर्देश दिया तथा संकेत दिया कि नोटिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मामले पर सोमवार या मंगलवार को सुनवाई की जा सकती है। यह विवाद उस समय और गहरा गया जब विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर अलग-अलग दावे सामने आने लगे। ऋतव्रत बंद्योपाध्याय के नेतृत्व वाले गुट ने स्वयं को पार्टी का वास्तविक संगठन बताते हुए पार्टी के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर दावा किया, जबकि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला खेमा खुद को पार्टी का वैध नेतृत्व बताते हुए संगठन और उसकी संपत्तियों पर अपना अधिकार बनाए हुए है। इसी राजनीतिक खींचतान के बीच पार्टी के बैंक खातों का संचालन भी विवाद का केंद्र बन गया।

सूत्रों के अनुसार, पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने संबंधित बैंक को पत्र लिखकर खातों के संचालन पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद दूसरे गुट की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बैंक को निर्देश दिया कि फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के तीनों खातों से किसी भी प्रकार का लेन-देन न होने दिया जाए। पुलिस ने खातों से संबंधित दस्तावेज भी मांगे हैं, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि वर्तमान परिस्थितियों में खातों के संचालन का वैधानिक अधिकार किसके पास है। इसी कार्रवाई को ममता बनर्जी गुट ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि पुलिस को पार्टी के बैंक खातों के संचालन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। जानकारी के अनुसार, जिन खातों को लेकर विवाद चल रहा है उनमें कुल लगभग 440 करोड़ रुपये जमा हैं। इनमें से करीब 260 करोड़ रुपये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के मुख्य खाते में हैं, जबकि लगभग 180 करोड़ रुपये गोवा और त्रिपुरा इकाइयों के खातों में जमा बताए जा रहे हैं। फिलहाल इन तीनों खातों से धन निकासी, भुगतान और अन्य वित्तीय लेन-देन पर रोक लगी हुई है। इससे पार्टी की नियमित संगठनात्मक गतिविधियों, चुनावी तैयारियों और प्रशासनिक खर्चों पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हाईकोर्ट ने अभी मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अदालत ने केवल यह स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा और उसके बाद ही किसी अंतरिम राहत या अंतिम आदेश पर विचार किया जाएगा। न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह होगा कि वर्तमान परिस्थितियों में पार्टी के बैंक खातों के संचालन का वैधानिक अधिकार किसके पास है और पुलिस द्वारा खातों के लेन-देन पर रोक लगाने की कार्रवाई कानून के अनुरूप थी या नहीं।

मतदाता सूची पुनरीक्षण पर बढ़ा सियासी संग्राम, एसआईआर अभियान से पहले कांग्रेस और चुनाव आयोग आमने-सामने

बेंगलुरु। कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) अभियान को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। मंगलवार से शुरू होने वाले इस राज्यव्यापी अभियान से पहले कांग्रेस और चुनाव आयोग आमने-सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया की पारदर्शिता, उद्देश्य और क्रियान्वयन को लेकर कई सवाल उठाए हैं, जबकि चुनाव आयोग निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभियान शुरू करने की तैयारी पूरी कर चुका है। राज्य सरकार का कहना है कि जब तक कांग्रेस की ओर से उठाई गई आशंकाओं और आपत्तियों का संतोषजनक समाधान नहीं किया जाता, तब तक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा।

सोमवार को बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने चुनाव आयोग से स्पष्ट जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसे पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और सभी राजनीतिक दलों के विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि कांग्रेस ने एसआईआर अभियान को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग को पहले उन सभी बिंदुओं पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। यदि इन चिंताओं का समाधान किए बिना अभियान आगे बढ़ाया गया तो इससे मतदाता सूची की विश्वसनीयता को लेकर अनावश्यक विवाद खड़े हो सकते हैं।

प्रियांक खरगे ने बताया कि राज्य सरकार इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के साथ विस्तृत चर्चा करेगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से गलत तरीके से न हटे और पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष तथा पारदर्शी रहे। उनका कहना था कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची की शुद्धता जितनी आवश्यक है, उतना ही जरूरी यह भी है कि इस प्रक्रिया पर किसी प्रकार का संदेह न रहे।

दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने कर्नाटक में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 29 जून से 29 जुलाई तक पूरे राज्य में घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान निर्वाचन अधिकारियों की टीमें प्रत्येक घर तक पहुंचकर मतदाताओं की जानकारी का भौतिक सत्यापन करेंगी, नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ेंगी, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नामों की समीक्षा करेंगी तथा मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने का प्रयास करेंगी।

चुनाव आयोग का कहना है कि यह नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाना है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अंबु कुमार भी इस अभियान को लेकर बेंगलुरु में संवाददाता सम्मेलन करेंगे, जिसमें एसआईआर की पूरी प्रक्रिया, दिशा-निर्देश और नागरिकों की भूमिका की जानकारी दी जाएगी। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है और इसमें सभी नागरिकों तथा राजनीतिक दलों के सहयोग की अपेक्षा की जाती है।

इस बीच कांग्रेस ने भी राज्यभर में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी ने अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और बूथ स्तर के पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पुनरीक्षण अभियान के दौरान पूरी सतर्कता बरतें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम अनुचित तरीके से सूची से हटाया न जाए। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि यदि कहीं भी मतदाता सूची में अनियमितता, गलत सत्यापन या किसी प्रकार की प्रक्रिया संबंधी त्रुटि दिखाई दे तो उसकी तत्काल जानकारी संबंधित निर्वाचन अधिकारियों और पार्टी नेतृत्व को दी जाए। कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है और इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या पक्षपात चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर सकता है। पार्टी चाहती है कि चुनाव आयोग पहले उसके द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का जवाब दे और उसके बाद ही व्यापक स्तर पर पुनरीक्षण अभियान चलाया जाए। वहीं चुनाव आयोग का रुख है कि यह प्रक्रिया कानून और निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित की जा रही है तथा इसका उद्देश्य केवल मतदाता सूची को अद्यतन बनाना है। एसआईआर अभियान को लेकर शुरू हुआ यह विवाद आने वाले दिनों में और राजनीतिक रूप ले सकता है। एक ओर कांग्रेस पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रही है, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग अपने कार्यक्रम के अनुसार अभियान आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।

हनीमून हत्याकांड में सोनम रघुवंशी को राहत बरकरार, मेघालय हाईकोर्ट ने जमानत रद्द करने से किया इनकार

शिलांग। देशभर में चर्चित रहे 'हनीमून मर्डर' मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। मेघालय हाईकोर्ट ने सोमवार को शिलांग की निचली अदालत द्वारा अप्रैल 2026 में दी गई जमानत को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि निचली अदालत द्वारा जमानत देने के आधारों में ऐसा कोई कानूनी दोष नहीं है, जिसके कारण उसके आदेश में हस्तक्षेप किया जाए। यह फैसला ऐसे समय आया है जब इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई पर पूरे देश की नजर बनी हुई है।

मामला मई 2025 में सामने आए उस सनसनीखेज हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें नवविवाहित दंपती के हनीमून के दौरान पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने पत्नी सोनम रघुवंशी को इस कथित हत्या की मुख्य आरोपी बनाया था। इस मामले ने उस समय पूरे देश में व्यापक चर्चा बटोरी थी और इसे 'हनीमून मर्डर केस' के नाम से जाना जाने लगा। पुलिस का आरोप है कि राजा रघुवंशी की हत्या एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी, जबकि बचाव पक्ष लगातार इन आरोपों को चुनौती देता रहा है। मामले का ट्रायल अभी जारी है और आरोपों की अंतिम सत्यता पर अदालत का निर्णय आना बाकी है। मेघालय हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील पर दोनों पक्षों की दलीलें दस दिनों से अधिक समय तक विस्तार से सुनीं। विस्तृत सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 10 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को सुनाए गए निर्णय में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील

को अस्वीकार करते हुए निचली अदालत के आदेश को यथावत रखा। इसके साथ ही सोनम रघुवंशी की जमानत फिलहाल बरकरार रहेगी। सोनम रघुवंशी को अप्रैल 2026 में शिलांग के अतिरिक्त उपायुक्त (न्यायिक) की अदालत ने जमानत प्रदान की थी। उस समय अदालत ने पाया था कि पुलिस गिरफ्तारी की प्रक्रिया के दौरान कानून द्वारा निर्धारित आवश्यक प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन नहीं कर सकी। अदालत के अनुसार, आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के आधारों की प्रभावी और स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, जिससे उसके संवैधानिक और कानूनी बचाव के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसी आधार पर अदालत ने माना था कि जमानत दिए जाने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं। निचली अदालत ने अपने आदेश में पुलिस की एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक त्रुटि का भी उल्लेख किया था। अदालत के अनुसार, आरोपी से संबंधित दस्तावेजों, गिरफ्तारी के औचित्य की जांच सूची तथा केस डायरी के अंशों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की हत्या से संबंधित धारा 103(1) का उल्लेख किए जाने के स्थान पर गलती से धारा 403(1) लिख दी गई थी। अदालत ने माना कि इतनी गंभीर प्रकृति के मामले में आरोपों से संबंधित गलत कानूनी धारा का उल्लेख आरोपी के अधिकारों को प्रभावित करता है, क्योंकि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि उसे किस अपराध और किस कानूनी प्रावधान के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रक्रियात्मक त्रुटि को जमानत दिए जाने के प्रमुख आधारों में शामिल किया गया था। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि निचली अदालत ने केवल तकनीकी आधार पर जमानत प्रदान की है, जबकि मामला अत्यंत गंभीर अपराध से जुड़ा है। सरकार का कहना था कि हत्या जैसे गंभीर मामले में केवल दस्तावेजी त्रुटि को आधार बनाकर आरोपी को जमानत देना उचित नहीं है और इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानून का पालन करना पुलिस की जिम्मेदारी है और यदि आरोपी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने फिलहाल केवल जमानत से जुड़े कानूनी पहलुओं पर निर्णय दिया है और मामले के गुण-दोष या आरोपी के दोषी अथवा निर्दोष होने पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसका अर्थ यह है कि जमानत मिलने से आरोपी को दोषमुक्त नहीं माना जाता और न ही इससे मुकदमे के अंतिम परिणाम पर कोई प्रभाव पड़ता है। हत्या के आरोपों पर अंतिम फैसला ट्रायल कोर्ट में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर ही होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब सोनम रघुवंशी की जमानत यथावत रहेगी, जबकि राज्य सरकार के पास यदि वह उचित समझे तो इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का विकल्प खुला रहेगा। वहीं, बहुचर्चित 'हनीमून मर्डर' मामले का मुकदमा अपने निर्धारित कानूनी क्रम के अनुसार आगे बढ़ेगा, जहां अभियोजन और बचाव पक्ष अपने-अपने साक्ष्य एवं तर्क अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

चढ़ावे की चोरी के दोषी बख्शे न जाएं

अयोध्या में राम मंदिर में भक्तों द्वारा दिए दान और कीमती सामान की हेराफेरी की घटनाओं ने देश-विदेश के रामभक्तों को विचलित किया है। कभी आमजन में कहा जाता था कि 'भगवान से डर', लेकिन पैसे की हवस देखिए कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े चंद लोगों ने भगवान के घर में चोरी करने में कोई डर महसूस नहीं किया। ये प्रबंधन व व्यवस्था की पारदर्शिता की खोट तो है ही, मानवीय मूल्यों के पतन की पराकाष्ठा भी है कि मंदिर में चढ़ावे की देखरेख को तैनात लोग ही चोरी-चकारी में लिप्त हो जाएं। इस मामले में विपक्ष के तीखे हमले और जनाक्रोश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए आनन-फानन में एसआईटी गठित की, रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी, प्राथमिकी दर्ज की और वीरवार को प्रबंधन से जुड़े आठ कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी हो गई। लेकिन अपने आराध्य राम के चढ़ावे की चोरी से आहत भक्तों के जख्मों पर शायद तभी मरहम लगेगी, जब दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। निश्चित ही यह चोरी का प्रकरण भाजपा व संघ को परेशान करने वाला है। उस राजनीतिक दल के लिये, जिसके कभी दो सांसद हुआ करते थे और राम मंदिर की मुहिम से हासिल जनसमर्थन से केंद्र व तमाम राज्यों में उसकी सरकारें बनी हैं। खासकर, भाजपा के लिए यह मुद्दा परेशानी का सबब हो सकता है क्योंकि राम जन्म भूमि वाले प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जिस मुद्दे को लेकर भाजपा राज्य की सत्ता में आती रही है, उस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर होगा। निस्संदेह, इस प्रकरण से राम भक्तों की आस्था को गहरी चोट तो पहुंची है। सवाल राम मंदिर ट्रस्ट की नाकामी पर भी उठेंगे कि उसने समय रहते इस चोरी को क्यों नहीं पकड़ा। बेहतर होता कि दोषियों के खिलाफ ट्रस्ट की तरफ से स्वतः प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जाती। सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर क्यों ट्रस्ट चंदे की रकम का हिसाब-किताब विश्वसनीय तरीके से नहीं रख पाया।

निश्चय ही इस प्रकरण से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की साख भी दांव पर लगी है। वह उन भक्तों की भावनाओं की रक्षा नहीं कर पाया, जिन्होंने मंदिर निर्माण से लेकर अब तक दिल खोलकर दान दिया। जब चंदा प्रबंधन से जुड़े लोगों के घर से लाखों की नकदी बरामद हुई और चोरी के पैसे से जमीन खरीदने के आरोप सामने आए तो भक्तों की आस्था पर आंच आना स्वाभाविक ही है। आरोप सिर्फ नकदी के हेरफेर के ही नहीं लगे बल्कि कीमती गहनों को खुर्दबुर्द करने के भी लगे। वहीं प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के दौरान दान में मिली चांदी की छड़ों के गायब होने का भी आरोप है। बहरहाल, 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले सामने आए इस विवाद ने प्रदेश में राजनीतिक हलचल मचा दी है। विपक्ष जहां दोषियों पर समय रहते कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहा है, वहीं भाजपा इन आरोपों को अयोध्या को बदनाम करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश बता रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि जिन भक्तों ने मंदिर निर्माण के लिए पांच सौ साल तक इंतजार किया, उन्हें एसआईटी जांच अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने का इंतजार करना चाहिए। उनकी दलील है कि इस शर्मनाक मामले की तह तक जाने के लिये एक पारदर्शी और समय-सीमा के भीतर होने वाली जांच बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल चंदे के रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने और स्वतंत्र ऑडिट की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों के दान और धार्मिक आस्था से जुड़े मामले में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से यह प्रकरण देश के बड़े धार्मिक संस्थानों में चंदे के प्रबंधन में पारदर्शिता व सतर्कता की मांग करता है। चंदे का नियमित ऑडिट किया जाना, तकनीक आधारित प्रबंधन, डिजिटल ट्रैकिंग और स्वतंत्र निगरानी वाले आधुनिक सिस्टम की जरूरत को दर्शाता है। निस्संदेह, राम मंदिर भारत व विदेशों में बसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आकांक्षा का प्रतीक है। श्रद्धालुओं का भरोसा बनाये रखने के लिये हर आक्षेप की पारदर्शिता से जांच जरूरी है।

पंजाब में खिसकती सियासी ज़मीन के मायने

> पंजाब की राजनीति में हालिया मुद्दों के चलते विधानसभा चुनाव से कुछ माह पूर्व ही आम आदमी पार्टी के पक्ष में बना संतुलन हिल गया है। आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री पलटवार कर रहे हैं, वहीं भाजपा पैठ बनाने की फिराक में है। अकाली दल अकेले दम बड़ी ताकत नहीं। बेशक फूट के बावजूद कांग्रेस का आधार है। क्या सीएम इन हालात से पार पा सकेंगे?

पंजाब की राजनीति में पिछला हफ़्ता कुछ ज्यादा ही गर्म रहा। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन हाल ही में राज्य के दौरे पर थे; उन्होंने अमृतसर, लुधियाना व जालंधर का दौरा किया ताकि 2027 के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले चुनौतियों की थाह ले सकें। जैसे ही नबीन पंजाब से लौटे, एक पुराना वीडियो सामने आया जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला कृत्य करते दिख रहे हैं, जिसने हर ओर हलचल मचा दी।

अकाल तख्त, जिसे व्यापक तौर पर आस्था के मामलों में सिखों द्वारा सर्वोच्च सत्ता माना जाता है, ने इस वीडियो को लेकर मान को दोषी ठहराया है; विपक्षी दलों ने भी ऐसा ही किया। मान ने अपने बचाव में भाजपा-शासित गुड़गांव की एक लैब से मिली 'क्लीन चिट' का हवाला दिया-परंतु, जल्द ही हरियाणा पुलिस ने क्लीन चिट की एवज में पैसे के लेन-देन के आरोप में उस लैब के दो लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है।

क्या मान इस संकट से उबर पाएंगे? क्या इससे 'आप' को बड़ा नुकसान होगा, वह पार्टी जिसने दिल्ली में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जन-आंदोलन से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी या क्या पार्टी पिछले हफ़्ते के झटके से उबरकर संकट को अवसर में बदल पाएगी? पिछले हफ़्ते तक, ऐसा लग रहा था कि 'आप' आसानी से आगे बढ़ रही है और विपक्ष बिखरा पड़ा है, कोई दल गंभीर चुनौती पेश करने की स्थिति में नहीं। मुख्यमंत्री मान के बीच-बीच में शाम ढले होने वाले चुनावी दौरे शायद ही सतलुज नदी में तरंगें उठा पाए हैं (जिसमें अभी उफान नहीं आया था)। साथ ही, अरविंद केजरीवाल के मुफ़्त सुविधाओं के चतुर वादों के साथ-जो लगता है भाजपा की सफल रही रणनीति की नकल है-जिसमें महिलाओं को पैसे देना (अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रु. प्रतिमाह तो अन्य को

1,000 रु.) और सफ़ाई कर्मचारियों, स्कूल शिक्षकों व सरपंचों जैसे महत्वपूर्ण समूहों की शिकायतें दूर करने का वादा शामिल है, 'आप' एक ऐसा फ़ॉर्मूला तैयार कर रही है जिसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। पंजाब सांसें थामे इंतज़ार कर रहा है और सवाल है कि क्या वीडियो से छिड़ी राजनीतिक लड़ाई इस सप्ताह भी जारी रहेगी। पिछले हफ़्ते तक, भाजपा को दौड़ में सिर्फ एक प्रतिभागी भर माना जा रहा था; लेकिन मची उथल-पुथल के बीच, वह महसूस कर रही कि शायद सियासी ज़मीन पर पांव जम सकता है। महत्वाकांक्षा को सदैव लोगों को साथ जोड़ने वाली चीज माना जाता है, लेकिन सवाल है कि क्या यह काफ़ी है? चुनाव में करीब छह माह बचे हैं, क्या भाजपा के पास विधानसभा की सभी सीटों पर लड़ने योग्य 117 उम्मीदवार हैं?

गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नबीन जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं का तो मानना है कि हो जाएंगे। 'द ट्रिब्यून' की ज़मीनी रिपोर्ट कहती है कि अकेले अपने दम पर न तो शिरोमणि अकाली दल और न ही भाजपा की स्थिति मज़बूत है; हां, गठबंधन होने पर, मुकाबला करने लायक हो सकते हैं। मेरी सहयोगी अदिति टंडन ने हाल ही में एक वरिष्ठ भाजपा नेता का हवाला दिया है, जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि 'राजनीति में कुछ भी संभव है'। इसीलिए गत सप्ताह, जब पंजाब में सियासी परिदृश्य बदल रहा है, सवाल है: क्या भाजपा व शिरोमणि अकाली दल, जिनमें 2020 में मोदी सरकार के कृषि कानूनों को लेकर कटु अलगाव हुआ था, आख़िर क्या फिर साथ आएंगे?

निश्चित तौर पर, 'राजनीति में एक हफ़्ता बहुत लंबा समय होता है', यह एक ऐसी आम बात है जिसे हर राजनेता मानता है-सिवाय राहुल गांधी के, जिनके पास शायद अन्य ज़्यादा ज़रूरी काम हैं, जबकि बीते हफ़्ते ही दिल्ली में पंजाब के नए प्रदेशाध्यक्ष को लेकर अहम बातचीत बमुश्किल पूरी हो पाई। याद रहे ,हाल ही में शहरी निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, जिससे पता चलता है कि भले ही राज्य में पार्टी बंटी है- मुख्यमंत्री पद के कम से कम पांच दावेदार हैं-फिर भी कांग्रेस की विचारधारा के प्रति लोगों में थोड़ी-बहुत वफ़ादारी अभी भी बची है।

अकाली दल के लिए बड़ी चुनौती है- क्या पंजाब के लोग उसे 'बेअदबी' के दोषियों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई न करने के लिए माफ़ कर पाएंगे? यह घटना 2015 में बरगाड़ी कस्बे में हुई थी, जब पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ने फटे मिले थे-तब अकाली सरकार थी।

निश्चित ही, पिछले हफ्ते विपक्ष भगवंत मान पर कथित वीडियो में वैसी ही गलती करने का आरोप लगा रहा है- जिसे मान और 'आप' ज़ोरदार ढंग से नकार रहे हैं। इसीलिए आगामी दिन चुनाव प्रचार की चाल-ढाल तय करेंगे। क्या मुख्यमंत्री इस मुश्किल दौर से पार पा सकेंगे और अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे? या क्या पंजाब 2027 में 'आप' के साथ वही करेगा जो उसने 2017 में अकाली दल के साथ किया था?

2027 की लड़ाई तो अभी शुरू ही हुई है। अकाल तख्त ने पहले ही आदेश दे दिया है कि पंजाब भर के ऐतिहासिक गुरुद्वारों में मान की निंदा वाले बैनर लगाए जाएं। कई जगह इस पर अमल हो भी गया; लेकिन ऐसी खबरें भी हैं कि कुछ स्वतंत्र प्रबंधन व सिंह सभा से जुड़े गुरुद्वारों में अभी ऐसा नहीं किया। स्थिति अभी भी साफ़ नहीं है।

एक और तथाकथित पार्टी है, 'वारिस पंजाब दे', जिसके सांसद अमृतपाल सिंह खडूर साहिब सीट से तब चुने गए थे जब वे असम की जेल में थे व अभी वहीं हैं। पंजाब में हालात बदल रहे, नए माहौल में इस दल की स्थिति क्या होगी?

बीते हफ्ते जब हालात धुंधला रहे थे और लोग सोच रहे थे कि आगे क्या होगा; राज्य का परिदृश्य है कि सूबा एक ऐसी धुरी पर घूम रहा है जिसे उसने खुद नहीं बनाया। अमृतसर में ' द ट्रिब्यून' के पत्रकार पवन के. जायसवार का कहना है कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर रोज़ाना हेरोइन और छोटे हथियारों की बरामदगी बढ़ रही है; पुलिस अफसरों का कहना है कि सीमा पार से आने वाले ड्रोन अत्याधुनिक हो रहे, जो कम ऊंचाई पर उड़कर रडार से बच सकते हैं और नशा एवं हथियारों की बड़ी खेप लाने में सक्षम हैं।

जालंधर से अपर्णा बनर्जी की द्वारा की गईं खबरें जिनमें हेरोइन की वजह से पूरे के पूरे परिवार खत्म होना नशे की राक्षसी जकड़ दर्शाती है। आप का अभियान 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' स्वागत योग्य है क्योंकि यह संकट को काफी हद तक उजागर करता है, लेकिन चुनौती इतनी बड़ी है कि पुनर्वास का काम सिर्फ़ आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं किया जा सकता। पंजाब को बचाना है, तो एक व्यापक कार्ययोजना के लिए सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष, दोनों को, साथ आना होगा। कभी-कभी स्थिति तब बदतर हो जाती है-जब नशा तस्करी के साथ हथियारों की तस्करी भी मिल जाए। पिछले हफ़्ते भाजपा ने अमृतसर से अपने एक स्थानीय वरिष्ठ नेता को बर्खास्त कर दिया, जब उसके बेटे के पास से-जो कथित तौर पर नशे का आदी है-बीएसएफ ने एके-47 समेत 26 आधुनिक हथियार बरामद किए।

शायद गत सप्ताह का आखिरी जिक्र मेरे साथियों नेहा सैनी और राजमीत सिंह की खबरों से होना चाहिए। उन्होंने गौर किया है कि राजनीतिक पार्टियों को वर्तमान में फ़ायदा उठाने के लिए इतिहास का आह्वान करना पसंद है-चाहे यह 2022 के चुनाव में आप का शहीद भगत सिंह के नाम का उपयोग करना हो या आज भाजपा द्वारा महाराजा रणजीत सिंह के 'सरकार-ए-ख़ालसा' का जिक्र करना (ऐसा सिख राज्य जो धर्मनिरपेक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाला था)।

तो जैसा कि पंजाब में होता है, अतीत और वर्तमान आपस में घुले-मिले हैं, वैसे ही जैसी एक-दूजे में समा जाने वाली यहां की नदियां। सवाल है कि क्या ये नदियां समुद्र की राह खोज पाएंगी और कैसे।

प्रेरणा

मृत्यु का सत्यः जीवन की सबसे बड़ी और निष्पक्ष वास्तविकता

युद्ध केवल तलवारों की टकराहट का नाम नहीं होता, बल्कि वह मनुष्य के साहस, विवेक, धैर्य और जीवन-दर्शन की भी परीक्षा लेता है। इतिहास में ऐसे अनेक सम्राट हुए जिन्होंने युद्ध जीते, साम्राज्य स्थापित किए और अपार वैभव अर्जित किया, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे थे जिन्होंने विजय के क्षण में भी जीवन के शाश्वत सत्य को समझा। फारस के प्रसिद्ध सम्राट नौशेरवां उन्हीं महान शासकों में गिने जाते हैं। उनकी न्यायप्रियता और गहरी बुद्धिमत्ता की चर्चा आज भी की जाती है। उनके जीवन से जुड़ी एक घटना हमें यह सिखाती है कि संसार में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है और जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह जीवन को भी अधिक सार्थक ढंग से जीना सीख जाता है।

एक बार युद्ध अपने चरम पर था। रणभूमि में दोनों पक्षों के सैनिक पूरे साहस और कौशल के साथ युद्ध कर रहे थे। चारों ओर तलवारों की चमक, घोड़ों की टापें और रणभेरी की आवाज़ गूंज रही थी। दूसरी ओर युद्ध शिविर में सम्राट नौशेरवां अपने मंत्रियों और सलाहकारों के साथ आगे की रणनीति पर विचार कर रहे थे। तभी अचानक शिविर के बाहर हलचल मच गई। एक गुप्तचर तेज़ी से दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। उसने सम्राट को प्रणाम करते हुए कहा, "बादशाह सलामत, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपका सबसे बड़ा शत्रु युद्ध के मैदान में हमारी सेना से लड़ते हुए मारा गया। अब विजय निश्चित रूप से हमारी होगी।"

सामान्यतः कोई भी राजा ऐसी सूचना सुनकर प्रसन्न हो जाता, विजय का उत्सव मनाने का आदेश देता और अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाता। लेकिन नौशेरवां का उत्तर बिल्कुल अलग था। उन्होंने शांत और गंभीर स्वर में कहा, "इसमें खुशखबरी जैसी कौन-सी बात है? जो इस संसार में जन्म लेता है, उसका एक दिन जाना निश्चित है। यदि तुम मुझे यह समाचार सुनाते कि मैं और मेरा वंश अमर हो गया है, तब यह सचमुच मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होती। मृत्यु तो अटल सत्य है। आज वह गया है, कल हमारी बारी भी आएगी। इसलिए मृत्यु में न तो अत्यधिक हर्ष होना चाहिए और न ही किसी के अंत पर अहंकार।"

सम्राट के इन शब्दों में केवल दार्शनिक विचार नहीं थे, बल्कि जीवन का गहरा अनुभव छिपा था। वास्तव में मनुष्य मृत्यु को दूसरों के लिए तो सहज मान लेता है, लेकिन स्वयं के लिए उसे स्वीकार करना कठिन लगता है। यही कारण है कि जब किसी शत्रु की मृत्यु होती है तो लोग उसे अपनी जीत समझते हैं, जबकि मृत्यु किसी की हार या जीत नहीं होती। वह प्रकृति का नियम है, जो राजा और रंक, अमीर और गरीब, ज्ञानी और अज्ञानी सभी पर समान रूप से लागू होता है।

भारतीय दर्शन भी यही शिक्षा देता है। भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए उस सत्य पर शोक करना उचित नहीं जिसे बदला नहीं जा सकता। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। केवल शरीर बदलता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्यागकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। यह विचार मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करने का प्रयास करता है।

मृत्यु का स्मरण निराशा पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को अधिक सार्थक बनाने के लिए आवश्यक है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका समय सीमित है, तब वह व्यर्थ के अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और संग्रह की प्रवृत्ति को कम करने लगता है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि धन, पद, प्रतिष्ठा और शक्ति सब यहीं रह जाएंगे। साथ जाएगा तो केवल उसका कर्म, उसका चरित्र और लोगों के हृदय में छोड़ी गई उसकी स्मृति।

सम्राट नौशेरवां ने अपने गुप्तचर को अप्रत्यक्ष रूप से यही संदेश दिया कि किसी की मृत्यु पर उत्सव मनाना उचित नहीं है। युद्ध कभी-कभी परिस्थितियों की मजबूरी हो सकता है, लेकिन मानवता का धर्म यह कहता है कि शत्रु भी अंततः एक मनुष्य ही होता है। उसका भी परिवार, उसकी भी आशाएं और उसके भी सपने होते हैं। इसलिए किसी की मृत्यु को केवल विजय का उत्सव बनाकर देखना जीवन की गहराई को न समझ पाने का संकेत है। आज के समय में भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन में मनुष्य सफलता की दौड़ में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे अपने जीवन की अस्थिरता का स्मरण ही नहीं रहता। वह मान बैठता है कि धन और शक्ति ही सब कुछ हैं। लेकिन जब किसी प्रियजन का निधन होता है या स्वयं जीवन किसी कठिन मोड़ पर पहुंचता है, तब उसे महसूस होता है कि जीवन वास्तव में कितना क्षणभंगुर है। यदि हम प्रतिदिन कुछ क्षण यह सोचें कि एक दिन हमें भी इस संसार से विदा होना है, तो शायद हमारे व्यवहार में अधिक विनम्रता, करुणा और प्रेम आ जाए।

मृत्यु का सत्य हमें भयभीत नहीं करता, बल्कि जागरूक बनाता है। वह हमें बताता है कि समय का सदुपयोग करो, संबंधों को महत्व दो, दूसरों के प्रति दया रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, वह जीवन को अधिक स्वतंत्रता और संतुलन के साथ जीता है। उसे छोटी-छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता, न ही वह अनावश्यक प्रतिस्पर्धा में अपनी शांति खोता है।

मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह स्वयं को स्थायी मान लेता है। यही भ्रम उसे अहंकारी बनाता है। लेकिन मृत्यु इस भ्रम को तोड़ देती है और याद दिलाती है कि संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ऋतुएं बदलती हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और अंततः प्रत्येक जीवन भी परिवर्तन के उसी नियम का पालन करता है।

इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि मृत्यु के भय में जीने के बजाय जीवन के प्रत्येक क्षण को अर्थपूर्ण बनाया जाए। अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का पालन किया जाए। सत्य, ईमानदारी और करुणा को अपने जीवन का आधार बनाया जाए। जब मनुष्य ऐसा करता है, तब मृत्यु उसके लिए अंत नहीं रह जाती, बल्कि एक पूर्ण और सफल जीवन की स्वाभाविक परिणति बन जाती है।

सम्राट नौशेरवां की यह छोटी-सी घटना हमें सिखाती है कि सच्चा विजेता वह नहीं जो केवल युद्ध जीत ले, बल्कि वह है जो जीवन के शाश्वत सत्य को समझकर अहंकार से ऊपर उठ जाए। मृत्यु न किसी की शत्रु है और न किसी की मित्र; वह केवल प्रकृति का निष्पक्ष नियम है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह जीवन को अधिक शांत, अधिक विनम्र और अधिक सार्थक बना सकता है। यही इस प्रसंग का सबसे बड़ा संदेश है कि मृत्यु से डरने की नहीं, उसे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मृत्यु का स्मरण ही हमें सच्चे अर्थों में जीवन जीना सिखाता है।

'मौत से नहीं डरती', कह कर Bangladesh लौटने का ऐलान करने वाली Sheikh Hasina ने ढाका की राजनीति में खड़ा किया तूफान

भारत में निर्वासन का जीवन बिता रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भले ही यह घोषणा की हो कि वह इसी वर्ष अपने देश लौटेंगी और उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां यह संकेत दे रही हैं कि वहां उनकी प्रतीक्षा केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि संभवतः मृत्यु भी कर रही है। वर्ष 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से उनके खिलाफ मानवता विरोधी अपराधों के कई मामले दर्ज किए गए हैं और उन्हें मृत्युदंड तक सुनाया जा चुका है। ऐसे माहौल में उनकी वापसी केवल एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि बांग्लादेश की सत्ता, न्याय व्यवस्था और प्रतिशोध की राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा बन सकती है। हम आपको बता दें कि शेख हसीना ने अपने देश लौटने की इच्छा जताकर वहां की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। एक साक्षात्कार में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वह इसी वर्ष बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है और उनका लौटना किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का नहीं, बल्कि लोकतंत्र, कानून के शासन और मुक्ति संग्राम की भावना की पुनर्स्थापना का प्रश्न है।

साथ ही शेख हसीना ने अपनी पार्टी अवामी लीग को केवल एक संगठन नहीं बल्कि एक शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमला दरअसल बांग्लादेश की स्वतंत्रता की भावना पर हमला है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र कमजोर हो चुका है, कानून व्यवस्था समाप्त हो रही है, अर्थव्यवस्था संकट में है और उग्रवाद तेजी से फैल रहा है। उन्होंने वर्तमान तारीक रहमान नेतृत्व वाली सरकार तथा पूर्ववर्ती मोहम्मद यूनुस के अंतरिम शासन पर भी तीखा हमला बोला। उनका कहना था कि देश में आम लोगों के राजनीतिक अधिकारों का हनन हो रहा है। शेख हसीना ने अपने ऊपर चल रहे मामलों और संभावित मृत्युदंड को भी राजनीतिक साजिश बताया। हम आपको बता दें कि उनके खिलाफ मानवता विरोधी अपराधों के कई मामले चल रहे हैं और अदालत से उन्हें मृत्युदंड की सजा भी सुनाई जा चुकी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया अवैध, असंवैधानिक और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में पहले भी अनेक षड्यंत्रों और हमलों का सामना किया है। वर्ष 1975 में उन्होंने अपने माता पिता, भाइयों और लगभग पूरे परिवार को खो दिया था। इसके अलावा उन पर ग्रेनेड हमला भी हुआ, लेकिन हर कठिन परिस्थिति से निकलकर वह जनता के साथ खड़ी रहीं।

शेख हसीना के इस बयान के बाद बांग्लादेश की राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सत्तारुढ़ बीएनपी और विपक्षी जमात-ए-इस्लामी के नेताओं ने उनके दावों को राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया है। उनका कहना है कि शेख हसीना अपने समर्थकों को सक्रिय कर वर्तमान राजनीतिक स्थिति को अस्थिर करना चाहती हैं। बीएनपी से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि सरकार को उनके बयानों से कोई चिंता नहीं है क्योंकि वर्तमान सरकार को भारी जनसमर्थन प्राप्त है और जनता उसके साथ खड़ी है।

दूसरी ओर, हाल के महीनों में ढाका के राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी तेज हुई है कि प्रतिबंधित अवामी लीग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में फिर से सक्रिय हो रही है। इसी कथित पुनरुत्थान के कारण तारीक रहमान सरकार ने अवामी लीग के सदस्यों को स्थानीय चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भाग लेने की अनुमति दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम बांग्लादेश की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों का संकेत है। जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख एटीएम अजहरुल इस्लाम ने भी इस मुद्दे पर बीएनपी की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि क्या बीएनपी अवामी लीग को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही है।

हम आपको बता दें कि बांग्लादेश की राजनीति लंबे समय से तीव्र ध्रुवीकरण, प्रतिशोध और कठोर दमन के लिए जानी जाती रही है। वहां सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक विरोधियों पर मुकदमे, गिरफ्तारी, निर्वासन और कई मामलों में मृत्युदंड तक की घटनाएं सामने आती रही हैं। इस समय पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी अवामी लीग के खिलाफ व्यापक कार्रवाई का दौर चल रहा है। वर्ष 2025 में शेख हसीना को मानवता विरोधी अपराधों के मामले में मृत्युदंड सुनाया गया। उनके अनेक सहयोगियों पर भी मुकदमे चल रहे हैं। सरकार ने अवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था और उसके हजारों समर्थकों को जेलों में रखा गया है।

यदि शेख हसीना वास्तव में बांग्लादेश लौटती हैं तो सबसे पहले उन्हें तत्काल गिरफ्तार किए जाने की संभावना प्रबल मानी जा रही है। चूंकि उनके खिलाफ मृत्युदंड सहित कई फैसले पहले से मौजूद हैं, इसलिए सरकार उन पर कानूनी कार्रवाई को तेज कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी वापसी देश में भारी तनाव पैदा कर सकती है, क्योंकि अवामी लीग अब भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रभाव रखती है। उनकी गिरफ्तारी या कठोर दंड से उनके समर्थकों में व्यापक विरोध प्रदर्शन और हिंसक टकराव की स्थिति बन सकती है। दूसरी ओर यदि सरकार उन्हें खुली राजनीतिक गतिविधि की अनुमति देती है, तो अवामी लीग फिर से मजबूत होकर सत्ता संतुलन बदल सकती है। यही कारण है कि वर्तमान सत्ता पक्ष उनकी वापसी को राजनीतिक और सुरक्षा चुनौती के रूप में भी देख रहा है।

अभियान

बदरीविशाल की दिव्य शरण: जहाँ पंचशिलाओं में आज भी भक्तों को मिलता है श्रीहरि का साक्षात् स्पर्श

हिमालय की बर्फ से आच्छादित चोटियों के मध्य, जहाँ आकाश धरती का आलिंगन करता हुआ प्रतीत होता है, वहीं विराजमान है भगवान श्री बदरीविशाल का परम पावन धाम। यह केवल चारधाम यात्रा का एक पड़ाव नहीं, बल्कि वह दिव्य स्थान है जहाँ युगों से ऋषि, मुनि, देवता और सिद्ध पुरुष भगवान श्रीहरि की आराधना करते आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार वैकुण्ठ में भगवान विष्णु अपने भक्तों को कृपा-दृष्टि प्रदान करते हैं, उसी प्रकार बदरिकाश्रम में वे प्रत्येक श्रद्धालु को अपनी दिव्य उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। इस धाम की महिमा केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। यहाँ बहने वाली अलकनंदा की प्रत्येक लहर, हिमालय की प्रत्येक शिला और तपोभूमि का प्रत्येक कण भगवान नारायण की दिव्यता से ओत-प्रोत है। इन्हीं दिव्य चमत्कारों में सबसे अधिक पूजनीय हैं बदरीनाथ धाम की पंचशिलाएँ, जिन्हें सनातन परंपरा में स्वयं श्रीहरि का जीवंत स्वरूप माना गया है।

शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव ने एक बार अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को बदरिकाश्रम की महिमा बताते हुए कहा था कि इस धाम में स्थित पाँच दिव्य शिलाएँ साधारण पत्थर नहीं हैं। इनमें स्वयं भगवान विष्णु का नित्य निवास है। जो श्रद्धालु श्रद्धा और विश्वास के साथ इन शिलाओं का दर्शन करता है, उसके मन के विकार दूर होने लगते हैं, पाप क्षीण होने लगते हैं और उसका हृदय भगवान की भक्ति से भर उठता है। स्कन्द पुराण के वैष्णव खंड में इन पंचशिलाओं—नारद, वाराही, नृसिंह, गरुड़ और मार्कण्डेय—की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। इन शिलाओं का दर्शन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान की अनंत कृपा का साक्षात् अनुभव है। जब कोई श्रद्धालु भगवान बदरीविशाल के दर्शन कर मंदिर से बाहर निकलता है और अलकनंदा के तट की ओर बढ़ता है, तब उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि वह किसी साधारण स्थान पर नहीं, बल्कि देवताओं की तपोभूमि में चल रहा है। शीतल पर्वतीय वायु, वेद-मंत्रों की ध्वनि, मंदिर की घंटियों का मधुर नाद और अलकनंदा का कलकल प्रवाह मन को भीतर तक पवित्र कर देता है। यही वह वातावरण है जहाँ भगवान के महान भक्तों ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन स्थानों को युगों-युगों के लिए पावन बना दिया।

देवर्षि नारद का जीवन भगवान विष्णु के प्रति अनन्य प्रेम का प्रतीक है। वे निरंतर "नारायण-नारायण" का कीर्तन करते हुए तीनों लोकों में भगवान का संदेश पहुँचाते रहे, लेकिन उनके हृदय में एक ही अभिलाषा थी कि वे अपने आराध्य के प्रत्यक्ष दर्शन करें। इस दिव्य कामना को लेकर वे बदरिकाश्रम पहुँचे और अलकनंदा के किनारे स्थित एक विशाल शिला पर बैठकर घोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर केवल वायु का सेवन किया तथा वर्षों तक भगवान का अखंड स्मरण करते रहे। भक्त की यह तपस्या देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उन्होंने पहले वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर नारद की परीक्षा ली। जब नारद ने उस वृद्ध में भी भगवान का ही स्वरूप देखा, तब श्रीहरि अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और उन्हें दर्शन देकर अखंड भक्ति का वरदान दिया। तभी से वह स्थान 'नारद शिला' कहलाया। आज भी ऐसा विश्वास है कि जो भक्त इस शिला के दर्शन कर सच्चे मन से "ॐ नमो नारायणाय" का जप करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। भगवान के वराह अवतार की कथा धर्म की विजय का अमर संदेश देती है। जब हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया, तब सम्पूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया, दैत्य का संहार किया और पृथ्वी माता का उद्धार किया। किंतु इस महान विजय के बाद भी भगवान ने स्वयं को विजेता नहीं माना। वे सीधे बदरिकाश्रम पहुँचे और तपस्या में लीन हो गए। जिस शिला पर उन्होंने ध्यान किया, वह उनकी दिव्य ऊर्जा से पवित्र हो गई और 'वाराही शिला' के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह शिला हमें सिखाती है कि सच्चा पराक्रम वही है जिसके साथ विनम्रता जुड़ी हो।

गरुड़ जी की भक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का सर्वोत्तम उदाहरण है। वे शक्ति, साहस और सेवा के प्रतीक माने जाते हैं। अपनी माता विनता को दासत्व से मुक्त कराने के बाद भी उनके मन में कोई अभिमान नहीं था। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वे जीवनभर भगवान विष्णु की सेवा करें। इसी संकल्प को लेकर वे बदरिकाश्रम आए और एक पैर पर खड़े होकर वर्षों तक कठिन तपस्या की। हिमपात, वर्षा, तेज़ हवाएँ और कठोर पर्वतीय परिस्थितियाँ भी उनकी साधना को विचलित नहीं कर सकीं। अंततः भगवान श्रीहरि उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ ने भगवान से केवल सेवा माँगी। उन्होंने कहा, "प्रभु! मुझे अपना वाहन बना लीजिए ताकि मैं सदैव आपके चरणों के निकट रह सकूँ।" भगवान उनकी निष्काम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपना दिव्य वाहन बना लिया। जिस शिला पर उन्होंने तप किया था, वह 'गरुड़ शिला' के नाम से विख्यात हो गई। यह शिला आज भी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में पाने की नहीं, बल्कि प्रभु की सेवा करने की भावना होती है।

भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए प्रकट हुए भगवान नृसिंह का तेज इतना प्रचंड था कि हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी देवता उनके समीप जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। ब्रह्माजी और सभी देवताओं ने विनम्रता से प्रार्थना की कि प्रभु अपने उग्र स्वरूप को शांत करें। भगवान ने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार की और बदरिकाश्रम आकर ध्यान में लीन हो गए। यहाँ उनका दिव्य तेज शांत होकर करुणा में परिवर्तित हो गया। जिस शिला पर भगवान ने निवास किया, वही आज 'नृसिंह शिला' के रूप में पूजित है। भक्तों का विश्वास है कि इस शिला के दर्शन से भय, संकट और नकारात्मकता दूर होती है तथा भगवान का अभय आशीर्वाद प्राप्त होता है।

महर्षि मार्कण्डेय की भक्ति अत्यंत निष्काम और निर्मल थी। उन्होंने न स्वर्ग की कामना की, न सिद्धियों की और न ही यश की। वे केवल भगवान नारायण के चरणों में अनंत प्रेम चाहते थे। देवर्षि नारद के मार्गदर्शन पर वे बदरिकाश्रम पहुँचे और एक शिला पर बैठकर "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का दीर्घकाल तक जप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि ने उन्हें दर्शन दिए और वर माँगने को कहा। ऋषि ने विनम्रतापूर्वक कहा, "प्रभु! मेरे हृदय में आपकी भक्ति कभी कम न हो और इस शिला पर आपका दिव्य निवास सदैव बना रहे, ताकि आने वाले युगों में भी भक्त यहाँ आकर आपकी कृपा का अनुभव कर सकें।" भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण की और तभी से वह स्थान 'मार्कण्डेय शिला' कहलाया।

इन पाँचों शिलाओं का महत्व केवल उनकी पौराणिक कथाओं में नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक ऊर्जा में है जो आज भी वहाँ अनुभव की जाती है। अनेक संतों ने कहा है कि यदि कोई श्रद्धालु अहंकार छोड़कर, निष्काम भाव से भगवान बदरीविशाल के दर्शन करे और फिर इन पंचशिलाओं के समक्ष मौन होकर "ॐ नमो नारायणाय" का जप करे, तो उसके भीतर एक अद्भुत शांति का उदय होता है। ऐसा लगता है मानो भगवान स्वयं उसके मन की व्यथा सुन रहे हों। बदरीनाथ धाम यह भी सिखाता है कि भगवान केवल भव्य मंदिरों में ही नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रत्येक अंश में विद्यमान हैं। हिमालय की चोटियाँ उनकी तपस्या की साक्षी हैं, अलकनंदा उनकी करुणा का प्रवाह है और पंचशिलाएँ उनके दिव्य स्पर्श का अमिट प्रमाण हैं। यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त अपने साथ केवल प्रसाद ही नहीं ले जाता, बल्कि अपने भीतर नई श्रद्धा, नई ऊर्जा और नया विश्वास लेकर लौटता है।

सनातन धर्म का सार यही है कि भगवान अपने भक्तों से कभी दूर नहीं होते। वे कभी श्रीराम बनकर धर्म की रक्षा करते हैं, कभी श्रीकृष्ण बनकर प्रेम का संदेश देते हैं, कभी नृसिंह बनकर भक्त की रक्षा करते हैं और कभी बदरीपुरी की इन दिव्य शिलाओं में विराजकर युगों-युगों तक भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से इन पंचशिलाओं का स्मरण करता है, उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलने लगता है। उसके भीतर का अहंकार समाप्त होता है, मन निर्मल होता है और आत्मा भगवान के चरणों की ओर अग्रसर होने लगती है। इसीलिए बदरीनाथ की पंचशिलाएँ केवल तीर्थस्थल नहीं हैं, बल्कि भगवान श्रीहरि की जीवंत कृपा का वह दिव्य माध्यम हैं जहाँ पत्थर भी बोलते नहीं, फिर भी भक्त के हृदय में प्रभु की वाणी बनकर गूँज उठते हैं।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

मुख्यमंत्री ने उद्योग एवं निवेशकों का वीजीआरसी के डिस्कशन्स को डिसीजन में, आइडियाज को प्रोजेक्ट्स में और प्रोजेक्ट्स को प्रॉस्पेरिटी में परिवर्तित करने का आह्वान किया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विशिष्ट सोच तथा समय से आगे का विचार कर उसके इम्प्लिमेंटेशन की प्रतिबद्धता से भारत प्रत्येक क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ा है
- श्री नरेन्द्र मोदी की विजनरी लीडरशिप के कारण दुनिया के देश भारत के साथ विश्वसनीय मित्र के भाव से जुड़े हैं और अधिक से अधिक देश जुड़ रहे हैं
- प्रधानमंत्री ने बैलेंस्ड ग्रोथ का जो विचार दिया, उसे गुजरात ने वीजीआरसी से आगे बढ़ाया है, आज गुजरात 'ग्लोबल गेटवे टू द फ्यूचर' बना है
- वीजीआरसी केवल निवेश का प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि स्थानीय उद्योगों को वैश्विक अवसरों के साथ जोड़ने का सशक्त माध्यम है
- मध्य गुजरात को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग तथा इनोवेशन हब बनाने की दिशा में वीजीआरसी एक महत्वपूर्ण कदम बनेगी
- ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, फार्मा, एग्री-फूड प्रोडक्ट्स तथा एमएसएमई क्षेत्र में मध्य गुजरात का महत्वपूर्ण योगदान

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की चौथी कड़ी का शुभारंभ कराया

▸▸ उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर तथा राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की प्रेरक उपस्थिति

▸▸ वाइब्रेंट गुजरात अब केवल इन्वेस्टमेंट समिट नहीं, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप और इनोवेशन की प्रतीक : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

▸▸ वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस-मध्य गुजरात के मंच से राज्य के विकास, औद्योगिक शक्ति और भविष्य के अवसरों को उजागर किया गया

वडोदरा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मध्य गुजरात क्षेत्र की वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) का सोमवार को वडोदरा से शुभारंभ कराते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विशिष्ट सोच तथा समय से आगे का विचार कर उसका इम्प्लिमेंटेशन करने की प्रतिबद्धता के कारण भारत प्रत्येक क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की विजनरी लीडरशिप के कारण दुनिया के देश भारत के साथ विश्वसनीय मित्र के भाव से जुड़े हैं तथा अधिक से अधिक देश भी जुड़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 12 वर्ष के सफल सुशासन में भारत ने अर्थव्यवस्था, उद्योग तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। इतना ही नहीं; प्रधानमंत्री ने उद्योगों को रेड टैपिज्म से बाहर लाकर रेड कारपेट से 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे आगे बढ़ाते हुए राज्य के जिलों के औद्योगिक एवं स्थानीय विकास को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 'वोकल फॉर लोकल' तथा 'लोकल टू ग्लोबल' की मंशा रीजनल वाइब्रेंट कॉन्फ्रेंसों से पूरी हो रही है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने उद्योग जगत के अग्रणियों, निवेशकों तथा उद्यमियों से वीजीआरसी में होने वाले डिस्कशन को डिसीजन में, आइडियाज को प्रोजेक्ट्स में और प्रोजेक्ट्स को प्रॉस्पेरिटी में परिवर्तित करने के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान किया।

उन्होंने इस वीजीआरसी को केवल निवेश का प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि स्थानीय उद्योगों को वैश्विक अवसरों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बताते हुए जोड़ा कि मध्य गुजरात के 10 जिलों को समाहित करने वाली दो दिवसीय वीजीआरसी में राज्य के इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के नए अवसरों एवं भागीदारी को मंच देने का आयोजन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने वीजीआरसी को संतुलित विकास का नया मॉडल बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए बैलेंस्ड ग्रोथ के विचार को राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया है। मेहसाणा, राजकोट और सूरत में आयोजित तीन वीजीआरसी की सफलता के बाद अब मध्य गुजरात में दो दिवसीय चौथी वीजीआरसी आयोजित हो रही है। उन्होंने गौरव के साथ कहा कि अब तक आयोजित हुईं तीनों वीजीआरसी में कुल 9,499 एमओयू द्वारा लगभग 13.30 लाख करोड़ रुपए का निवेश राज्य में आया है।

मुख्यमंत्री ने मध्य गुजरात को राज्य के विकास का हृदय बताते हुए कहा कि वडोदरा, आणंद, खेडा, पंचमहाल, छोटाउदेपुर तथा दाहोद जैसे जिले मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, फार्मा, एग्री-फूड प्रोडक्ट्स और एमएसएमई क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

उन्होंने भूमिका देते हुए कहा कि वडोदरा पेट्रोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, ईवी इक्विपमेंट तथा टाटा एयरबस सी-295 जैसे एयरोस्पेस प्रोजेक्ट्स के कारण नए औद्योगिक क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहा है। आणंद देश का मिल्क कैपिटल है तथा अमूल ब्रांड विश्वभर में भारत की पहचान बना है और खेडा जिले में फूड प्रोसेसिंग व एमएसएमई क्षेत्र में बड़ी संभावनाएँ विद्यमान हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस बात का भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से वर्ष 2003 में शुरू हुई वाइब्रेंट गुजरात बिजनेस समिट की दो दशकों की सफलता से गुजरात आज ग्लोबल गेटवे टू द फ्यूचर बना है।

उन्होंने कहा कि जब इस प्रकार की बिजनेस समिट आयोजित करने का विचार भी कोई नहीं कर सकता था, तब श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वभर के निवेशकों को गुजरात लाने का सपना देखा था, जो आज साकार हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात आज बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बना है और ग्लोबल सप्लाई चेन में उद्योगों की भागीदारी मजबूत बनाने एवं उसे और गति देने के लिए राज्य सरकार ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2026 घोषित की है। इस पॉलिसी में एमएसएमई, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स तथा नए उद्योग क्षेत्रों के लिए अनेक इंडस्ट्री फ्रेंडली इंसेंटिव्स को शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि पहली बार 'चूज योर इंसेंटिव्स' जैसी नई पहल इस पॉलिसी में की गई है, जिसमें उद्योग अपनी आवश्यकता के अनुसार इंसेंटिव्स का चयन कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गुजरात को पॉलिसी ड्रिवन स्टेट की पहचान दिलाई है। आज गुजरात मजबूत नीतिगत ढाँचे, गुड गवर्नेंस, आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा तेज निर्णय प्रक्रिया के कारण अग्रसर बना है और हमने पॉलिसी ड्रिवन स्टेट से विकसित भारत बनने की दिशा अपनाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत और ग्रीन ग्रोथ जैसे अभियानों के साथ गुजरात नई अर्थव्यवस्था के निर्माण में अग्रिम योगदान दे रहा है। उन्होंने विकसित गुजरात से विकसित भारत @2047 का संकल्प साकार करने के लिए उद्योग, व्यापार तथा इनोवेशन की शक्ति के साथ आगे बढ़ने का संकल्प व्यक्त किया।

केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल

इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कोई भी निवेशक निवेश करने से पहले विचार करता है कि जहाँ वह निवेश कर रहा है, वह स्थान निवेश के लिए कितना उचित है। क्या यह वह स्थान है, जहाँ उसका उद्योग विश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इस उद्देश्य को और सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। निवेशकों को यह विश्वास होना चाहिए कि उन्हें सरकार की स्थिर नीतियाँ, विश्वसनीय बिजली, इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा तथा उद्योग संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था मिलेंगी, जिससे उनका उद्योग सफल हो। यह विश्वास ही गुजरात की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय से गुजरात में पॉलिसी स्टेबिलिटी, कुशल प्रशासन और विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जो इसे वैश्विक निवेश का प्रमुख केन्द्र बनाता है। वाइब्रेंट गुजरात उसी विचार का प्रतीक है, जहाँ सरकार तथा उद्योग विकास के भागीदार हैं। यह विचार ही आज भारत की विकास यात्रा का आधार बना है।

उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए रिलायेबल पावर बहुत आवश्यक है। रिलायेबल पावर ही मजबूत अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। गुजरात इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देता है। उद्योगों, एमएसएमई, डेटा सेंटर, मेट्रो रेल और नई तकनीकों के लिए बिजली व्यवस्था का उचित आयोजन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत की सबसे पीक पावर डिमांड इस वर्ष 271 गीगावाट रही है, जिसकी हमने पूर्ति की है। हमारी 284 गीगावाट तक की तैयारी थी। आगामी वर्षों में डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहनों और एआई के कारण पावर डिमांड बढ़ेगी। इसलिए हमने 300 गीगावाट तक की तैयारी कर रखी है। यह केवल तकनीकी आयोजन नहीं, बल्कि वर्षों की योजना और उसमें सुधार तथा पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो योजनाएँ बनीं, उसका परिणाम है।

उन्होंने कहा कि आज भारत वन नेशन, वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी के आधार पर ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ा रहा है। वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाओं के समय भी हमने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाए रखा है तथा आर्थिक स्थिरता भी रही है। भारत को लेकर आशंकाएँ व्यक्त की जा रही थीं, लेकिन हमने भारत में स्थिरता बनाकर रखी है।

उन्होंने कहा कि गुजरात प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। यह पावर सरप्लस राज्य है। रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में भी गुजरात देश का नेतृत्व कर रहा है। राज्य में 50 गीगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी स्थापित की गई है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में गुजरात ने आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण भी स्थापित किया है। गुजरात ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि शहरी विकास क्षेत्र में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पीएमएवाई (शहरी) एक बहुत बड़ी योजना घोषित की गई है। वर्तमान में पीएमएवाई एवं पीएमएवाई 2.0 अंतर्गत 1 करोड़ 27 लाख से अधिक आवास मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 98.6 लाख आवास पूर्ण कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। गुजरात में भी इन योजनाओं के अंतर्गत 11.5 लाख से अधिक आवासों को मंजूरी दी गई है।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

ऐतिहासिक नगरी वडोदरा में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस-मध्य गुजरात के मंच से गुजरात के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा, "अब वाइब्रेंट गुजरात केवल एक इन्वेस्टमेंट समिट नहीं, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का प्रतीक बन गई है। यह इनोवेशन को बढ़ावा देने वाला एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात लगातार आर्थिक बदलाव का साक्षी बन रहा है।"

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य गुजरात एक ऐसी भूमि है, जहां इतिहास, नवाचार और संस्कृति एक साथ साँस लेते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य गुजरात ने हर युग में देश को एक नई दिशा दिखाई है। वडोदरा की कला, कौशल, शिक्षा और नवाचार उसकी सबसे बड़ी ताकत है। विरासत से लेकर पर्यटन तक, इस क्षेत्र ने गुजरात का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन किया है। दुनिया को सहकारिता का मार्ग दिखाने वाला सहकारी आंदोलन भी इस भूमि से शुरू हुआ था।

उन्होंने पंचमहाल, महिसागर, दाहोद और छोटा उदेपुर की समृद्ध आदिवासी संस्कृति पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि नर्मदा जिले में स्थित दुनिया की सबसे ऊँची 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' आज पूरे भारत के गौरव का प्रतीक बन गई है।

मध्य गुजरात की औद्योगिक क्षमता पर प्रकाश डालते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, "हम न केवल इतिहास की गाथा कह रहे हैं, बल्कि भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं। गुजरात के कुल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में मध्य गुजरात क्षेत्र का योगदान लगभग 28 फीसदी है। वर्ष 2025-26 में यहां से 20.5 अरब डॉलर से अधिक के उत्पाद निर्यात किए गए हैं, जो दुनिया के अनेक देशों तक पहुंच रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "आज मध्य गुजरात में 65 से अधिक जीआईडीसी एस्टेट हैं, जिनमें 24,000 से अधिक औद्योगिक प्लॉट सक्रिय हैं। गुजरात के 92 फीसदी ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स, 70 फीसदी बेवरेज प्रोसेसिंग, 63 फीसदी फार्मास्युटिकल्स और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में मध्य गुजरात का महत्वपूर्ण योगदान है। हम न केवल ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहे हैं, बल्कि हम उसका नेतृत्व भी कर रहे हैं।"

उप मुख्यमंत्री ने कहा, "यह मध्य गुजरात की प्रगति की केवल शुरुआत भर है। सेंट्रल गुजरात इकोनॉमिक मास्टर प्लान के अंतर्गत आगामी 20 वर्षों की विकास ब्लूप्रिंट तैयार की गई है।"

उन्होंने कहा कि इस आयोजन के तहत छोटाउदेपुर को भारत का अगला स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हब बनाया जाएगा और वडोदरा को देश का सबसे बड़ा बायोइकोनॉमी हब बनाने की दिशा में काम चल रहा है।

उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "विकसित गुजरात औद्योगिक पॉलिसी 2026 के अंतर्गत आगामी पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है।"

उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी का अहम पहलू महिला सशक्तिकरण है। महिला उद्यमियों को 360-डिग्री सपोर्ट फ्रेमवर्क दिया जाएगा। उन्हें अतिरिक्त 1 फीसदी ब्याज सब्सिडी, करियर ब्रेक के बाद वापस आने वालीं महिलाओं के लिए स्किल रिफ्रेशर कोर्स और पांच वर्षों तक 75 फीसदी रेंटल असिस्टेंस जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

उन्होंने कहा कि मेगा और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के जरिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने और 3000 रोजगार के अवसरों का सृजन करने का लक्ष्य है। दिव्यांग भाई-बहनों को रोजगार देने वाली कंपनियों को भी राज्य सरकार की ओर से 5 से 10 वर्षों तक ईपीएफ रीइंबर्समेंट का संपूर्ण सहयोग दिया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा, "गुजरात ने उद्योगों के लिए तेज और पारदर्शी सुशासन का मॉडल स्थापित किया है। गत दो वर्षों में इंसेंटिव डिस्बर्समेंट में 55 फीसदी की वृद्धि हुई है और वह 7888 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।"

उन्होंने आगे कहा कि आवेदन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेजों में 41 फीसदी की कमी की गई है, लंबित फाइलों में 95 फीसदी की कमी दर्ज की गई है और आज रोजाना लगभग 392 आवेदन क्लियर हो रहे हैं। यह तेज कार्यान्वयन, पारदर्शिता और नीतिगत स्थिरता गुजरात को निवेश के लिए विश्वसनीय स्थान बनाते हैं।

निवेशकों को आमंत्रण देते हुए श्री हर्ष संघवी ने कहा, "वाइब्रेंट गुजरात का यह मंच केवल एमओयू पर हस्ताक्षर करने का स्थान नहीं है, बल्कि यह सपनों का साकार करने का अवसर है। मैं हर निवेशक, स्टार्टअप फाउंडर और उद्योग जगत के अग्रणियों को आमंत्रित करता हूं कि आइए, हम विकस की इस नई गाथा का हिस्सा बनें, अवसरों को निवेश में और साहस को समृद्धि में बदलें।"

उन्होंने आगे कहा, "माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत@2047' के संकल्प को साकार करने के लिए विकसित गुजरात का इंजन तीव्र गति से दौड़ रहा है। आइए, हम सभी मिलकर एक नया मध्य गुजरात बनाएं।"

वीजीआरसी के उद्घाटन सत्र में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, वरिष्ठ सचिव और उद्योग-व्यापर जगत के अग्रणी सहित विभिन्न देशों के राजदूत और बड़ी संख्या में युवा उद्यमी मौजूद रहे।

'क्लीन सिटी-ग्रीन सिटी' के संकल्प की ओर वडोदरा का मजबूत कदम

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की प्रेरक उपस्थिति में वडोदरा में 'पीएम ई-बस सेवा' योजना के तहत 30 एसी इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया

▸▸ वडोदरा शहर की जनता को प्रदूषण मुक्त और आधुनिक परिवहन सेवा की सौगात, कुल 250 इलेक्ट्रिक बसों के जरिए पर्यावरण संरक्षण का दृढ़ संकल्प

वडोदरा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की प्रेरक उपस्थिति में सोमवार को वडोदरा में आयोजित 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस' के दौरान जीएसएफसी गेट नंबर-1 से 30 नई एसी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

वडोदरा महानगर पालिका ने शहर को 'क्लीन सिटी-ग्रीन सिटी' बनाने के संकल्प के साथ केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'पीएम ई-बस सेवा' योजना के तहत इस पर्यावरण-अनुकूल परिवहन क्रांति की शुरुआत की है।

वडोदरा शहर की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पहले मंजूर की गई 100 बसों के स्थान पर अब कुल 250 एसी इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। इस योजना के पहले चरण में कुल 130 बसें आवंटित की जाएंगी, जिसके अंतर्गत इस सुविधा का प्रारंभ किया गया है।

ये इलेक्ट्रिक बसें 'जीरो एमिशन' टेक्नोलॉजी से सुसज्जित होने के कारण शहर में कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी और नागरिकों को शुद्ध हवा में यात्रा करने का लाभ मिलेगा। ये सभी बसें संपूर्ण वातानुकूलित (एसी) और आवाज-रहित होने से यात्रा अधिक सुखद और आरामदायक होगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैसेंजर काउंटिंग सिस्टम और ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, दुर्घटना के समय सुरक्षा के लिए फायर एक्सटिंग्विशर (अग्निशामक यंत्र) और फर्स्ट एड किट की सुविधा भी उपलब्ध है। ये बसें व्हीलचेयर एक्सेसिबल हैं। दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राथमिकता वाली सीटंध तथा महिलाओं के लिए विशेष 'पिंक सीटें' आरक्षित की गई हैं। चुनिंदा ब सों में हाइड्रोलिक लिफ्ट और रैम्प की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, आधुनिक यात्रा अनुभव के लिए डिजिटल टिकटिंग, लाइव ट्रैकिंग के लिए जीपीएस सिस्टम और अनाउंसमेंट के लिए 'पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम' कार्यरत रहेंगे। नागरिक नकद के अलावा यूपीआई, टिकटिंग कार्ड और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए टिकट खरीद सकते हैं।

बसों के सुचारु संचालन के लिए गोत्री, सयाजीगंज, निजामपुरा, सयाजीपुरा और मकरपुरा में विशेष चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉ. मनीषाबेन वकील, विधानसभा में मुख्य सचेतक श्री बालकृष्ण शुक्ल, मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, कई विधायक और पदाधिकारियों सहित अग्रणी उपस्थित रहे।

वडोदरा महानगर पालिका की यह पर्यावरण-अनुकूल पहल केवल यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को प्रदूषण मुक्त वातावरण देने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। इन इलेक्ट्रिक बसों के आगमन से वडोदरा के सार्वजनिक परिवहन ढांचे में नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

दिल्ली की नई ईवी नीति से परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स माफी से लेकर लाखों की सब्सिडी तक

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति-2026 को मंजूरी दे दी गई। इस नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को आकर्षक बनाने के लिए टैक्स में भारी छूट, प्रत्यक्ष सब्सिडी, स्क्रैपिंग प्रोत्साहन और चरणबद्ध तरीके से पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की व्यापक योजना तैयार की गई है। सरकार का मानना है कि इस नीति के लागू होने से न केवल राजधानी में प्रदूषण का स्तर कम होगा, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन प्रणाली को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई ईवी नीति 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी और इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक दिल्ली को स्वच्छ, आधुनिक और प्रदूषण-मुक्त परिवहन व्यवस्था की दिशा में अग्रसर करना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली लंबे समय से वायु प्रदूषण की गंभीर चुनौती का सामना कर रही है और परिवहन क्षेत्र से निकलने वाला धुआं इसके प्रमुख कारणों में शामिल है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग पेट्रोल, डीजल और सीएनजी आधारित वाहनों की बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ईंधन पर होने वाला खर्च भी कम किया जा सके। नई नीति के तहत सबसे बड़ी राहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले उपभोक्ताओं को दी गई है। सरकार ने घोषणा की है कि 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। इससे नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को बड़ी आर्थिक राहत प्राप्त होगी और उनकी शुरुआती लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। सरकार का मानना है कि टैक्स छूट मिलने से मध्यम वर्ग के उपभोक्ता भी इलेक्ट्रिक कारों की ओर तेजी से आकर्षित होंगे। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने विशेष प्रोत्साहन योजना तैयार की है। नई नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल खरीदने वालों को पहले तीन वर्षों तक चरणबद्ध तरीके से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पहले वर्ष वाहन खरीदने पर 30 हजार रुपये की सहायता मिलेगी। दूसरे वर्ष यह राशि 20 हजार रुपये होगी, जबकि तीसरे वर्ष 10 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि यह योजना युवाओं, छात्रों और रोजमर्रा के उपयोगकर्ताओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को भी नई नीति में विशेष महत्व दिया गया है। ऑटो चालकों और व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए पहले वर्ष 50 हजार रुपये, दूसरे वर्ष 40 हजार रुपये और तीसरे वर्ष 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक ट्रकों की खरीद पर भी एक लाख रुपये तक का प्रोत्साहन प्रस्तावित किया गया है, जिससे माल परिवहन क्षेत्र में भी स्वच्छ ऊर्जा आधारित वाहनों का उपयोग बढ़ सके। सरकार ने राजधानी में पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की स्पष्ट समयसीमा भी तय कर दी है। नई नीति के अनुसार 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा का ही नया पंजीकरण किया जाएगा। इसके बाद नए पेट्रोल और सीएनजी ऑटो का पंजीकरण बंद हो जाएगा। सरकार का मानना है कि सार्वजनिक परिवहन के इस महत्वपूर्ण हिस्से को इलेक्ट्रिक बनाने से प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी और परिचालन लागत भी घटेगी। इसी क्रम में दोपहिया वाहनों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल 2028 से राजधानी में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही नया पंजीकरण किया जाएगा। यानी इसके बाद पेट्रोल आधारित नई मोटरसाइकिलों और स्कूटरों का पंजीकरण नहीं होगा। इस कदम को राजधानी के परिवहन क्षेत्र में सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इसके लिए चार्जिंग नेटवर्क, बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं और आवश्यक आधारभूत ढांचे का विस्तार भी समानांतर रूप से किया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। नई ईवी नीति में पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए भी विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। यदि कोई वाहन मालिक बीएस-4 या उससे नीचे के मानक वाले अपने पुराने वाहन को अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्र पर जमा कर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, तो उसे एक लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि पुराने प्रदूषणकारी वाहन सड़कों से हटें और उनकी जगह स्वच्छ तकनीक वाले इलेक्ट्रिक वाहन लें। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि हाइब्रिड वाहनों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह नीति पूरी तरह बैटरी आधारित इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। सरकार ने ईवी से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू करने की घोषणा की है। इस पोर्टल के माध्यम से वाहन खरीदने वाले नागरिक सब्सिडी, टैक्स छूट, स्क्रैपिंग प्रोत्साहन तथा अन्य सभी सरकारी लाभों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

पश्चिम रेलवे वसई रोड के रास्ते वलसाड वेलांकन्नि – डहाणू रोड के बीच चलाएगी स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से वलसाड – वेलांकन्नि – डहाणू रोड स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार हैः

ट्रेन संख्या 09030/09029 वलसाड – वेलांकन्नि – डहाणू रोड स्पेशल [02 फेरे]

ट्रेन संख्या 09030 वलसाड–वेलांकन्नि स्पेशल वलसाड से शुक्रवार, 03 जुलाई, 2026 को 18.25 बजे प्रस्थान करेगी तथा रविवार को 10.00 बजे वेलांकन्नि पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09029 वेलांकन्नि – डहाणू रोड स्पेशल वेलांकन्नि से सोमवार, 06 जुलाई, 2026 को 00.30 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 10.30 बजे डहाणू रोड पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में पालघर, वसई रोड, पनवेल, लोनावला, पुणे, दौंड, सोलापुर, कलबुरगि, वाडी, यादगिर, कृष्णा, रायचूर, मंत्रालयम रोड, आदोनि, गुंतकल, गुत्ती, ताडिपत्रि, यर्रगुंटला, कड़पा, राजमपेटा, रेणिगुंटा, काटपाडी, वेलूर छावनी, तिरुवण्णामलै, विल्लुपुरम, तिरुप्पादिरिप्पुलियूर, चिदम्बरम, मइलाडुतुरै, तिरुवल्लूर, कारैक्काल, नागूर और नागप्पट्टिनम स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन संख्या 09030 का डहाणू रोड स्टेशन पर एक अतिरिक्त ठहराव होगा।

इस ट्रेन में स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09030 की बुकिंग 30.06.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात को निवेश, विकास और रोजगार क्षेत्र में अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए 8 नए औद्योगिक एस्टेट बनाने की घोषणा की

▸▸ गुजरात में उद्योगों के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खेड़ा, अहमदाबाद, पंचमहाल, छोटाउदेपुर और भावनगर जिले में 3611 एकड़ क्षेत्र में कार्यरत होंगे स्मार्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट

▸▸ खेड़ा के महीज, सरखेज, अंघाड़ी और महिसा, अहमदाबाद के मांडल, पंचमहाल के नदीसर, छोटाउदेपुर के ऊंडवा तथा भावनगर के मोणपुर में बनेंगे नए औद्योगिक एस्टेट

वडोदरा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने निवेश, विकास और रोजगार क्षेत्र में गुजरात को और भी विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) की वडोदरा में आयोजित चौथी कड़ी में विभिन्न जिलों में 8 नए औद्योगिक एस्टेट (जीआईडीसी) स्थापित करने की घोषणा की। राज्य के सर्वांगीण औद्योगिक विकास को अधिक गति देने के लिए इन स्मार्ट एस्टेट्स के द्वारा आधुनिक सुविधाएं, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। ये स्मार्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट खेड़ा, अहमदाबाद, पंचमहाल, छोटाउदेपुर और भावनगर जिले में 3611 एकड़ क्षेत्र में आकार लेंगे। तदनुसार, खेड़ा जिले के महीज जीआईडीसी को 130.3 एकड़ क्षेत्र में, कठलाल तहसील के सरखेज जीआईडीसी को 332.7 एकड़ क्षेत्र, महुधा तहसील के महिसा जीआईडीसी को 18.5 एकड़, गळतेश्वर तहसील के अंघाड़ी जीआईडीसी को 310.9 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, अहमदाबाद जिले के मांडल जीआईडीसी को 515.2 एकड़ क्षेत्र में, पंचमहाल जिले की गोधरा तहसील के नदीसर जीआईडीसी को 105.5 एकड़ क्षेत्र में, छोटाउदेपुर जिले की जेतपुर पावी तहसील के उंडवा जीआईडीसी को 247.1 एकड़ क्षेत्र में और भावनगर जिले की वल्भीपुर तहसील के मोणपुर जीआईडीसी को 1950.7 एकड़ क्षेत्र में नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई।

इस घोषणा के अंतर्गत गुजरात के विभिन्न जिलों में कुल 3611 एकड़ क्षेत्र में नए इंडस्ट्रियल एस्टेट विकसित किए जाएंगे। इस आयोजन से मध्य गुजरात में औद्योगिक निवेश को गति मिलेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा स्थानीय विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य उद्योगों के लिए प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं के साथ सुव्यवस्थित औद्योगिक एस्टेट्स का निर्माण, निवेशकों के लिए सरलता और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।

वीजीआरसी मध्य गुजरात-वडोदरा

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की रूसी महासंघ के व्यापार प्रतिनिधित्व में सरकारी संबंधों एवं वित्तीय क्षेत्र की प्रमुख श्री ज्लाटा अंतुशेवा के साथ फलदायी बैठक हुई

वडोदरा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा में चल रही मध्य गुजरात क्षेत्र की द्विदिवसीय वीजीआरसी के प्रथम दिन सोमवार को वन-टू-वन बैठकों की श्रृंखला के अंतर्गत भारत में रूस के व्यापार प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक आयोजित की।

इस बैठक में उन्होंने परिवहन, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, पेमेंट सिस्टम के अलावा भारतीय एमएसएमईस, आईएनआर-आधारित वित्तीय लेन-देन जैसे क्षेत्रों में तथा रूस की आर्केम (स्पेशियलिटी केमिकल्स) और यूरोकेम (उर्वरक) कंपनियों के साथ पारस्परिक सहभागिता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के संबंध में परस्पर चर्चा-विमर्श किया।

इस बैठक में मुख्य सचिव श्री मनोज दास, उद्योग विभाग की अपर मुख्य सचिव सुश्री ममता वर्मा, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री अश्विनी कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार तथा मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे उपस्थित रहे।

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस - वडोदरा

वडोदरा जीएसएफसी में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस अंतर्गत सेमिनार आयोजित हुआ

▸▸ छोटाउदेपुर को औद्योगिक स्तर पर ले जाकर 'स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हब' बनाने का रोडमैप तैयार होगा

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत @2047' के विजन को साकार करने के लिए गुजरात ने 'विकसित गुजरात' का मजबूत रोडमैप तैयार किया : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ भारत को ग्लोबल स्पोर्टिंग पावरहाउस बनाने में स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा : केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया

वडोदरा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गुजरात सरकार के विशिष्ट दृष्टिकोण 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट' अंतर्गत छोटाउदेपुर में सोमवार को स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हब और परंपरागत कौशल से औद्योगिक स्तर तक विषय पर वडोदरा जीएसएफसी में सेमिनार आयोजित किया गया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत @2047' के विजन को साकार करने के लिए गुजरात ने 'विकसित गुजरात' का मजबूत रोडमैप तैयार किया है। इसके अंतर्गत राज्य के संतुलित आर्थिक विकास के लिए पूरे गुजरात को कच्छ, सौराष्ट्र, कॉस्टल सौराष्ट्र, उत्तर, मध्य और सूरत – ऐसे छह प्रमुख इकोनॉमिक रीजन में विभाजित किया गया है। इन सभी क्षेत्रों के लिए फोकस सेक्टर निर्धारित किए गए हैं तथा उनकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने 12 वर्षों के लगातार कार्यकाल से लेकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल तक जो भी संकल्प सार्वजनिक रूप से व्यक्त किए, उन्हें धरातल पर साकार करके दिखाया है। इसी कारण आज निवेशकों का सरकार पर अटूट विश्वास बना है। एक समय देश में असंभव मानी जाने वाली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गुजरात में चार बड़े प्लांटों के साथ तेजी से विकसित हो रही है। देश में पहली बार राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति-2026 घोषित कर उद्योगों को कैपिटल सब्सिडी और बिजली दरों में अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुनने की देश में पहली बार अभूतपूर्व छूट प्रदान की है। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2003 से प्रारंभ हुए 'वाइब्रेंट गुजरात' प्लेटफॉर्म की सफलता के कारण आज यह वैश्विक स्तर का मंच बन चुका है, जिससे राज्य में होने वाले एमओयू का क्रियान्वयन 70 से 90 प्रतिशत तक की उच्च दर से हो रहा है। उद्योगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर राज्य सरकार हमेशा सक्रिय रहकर समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए तत्पर रहती है। उन्होंने देश और राज्य के विकास के लिए सभी से मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान किया; ताकि वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विकसित गुजरात का सपना साकार हो सके। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश की उभरती हुई स्पोर्ट्स इकोनॉमी में स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एक मजबूत स्तंभ के समान है। भारत सरकार खेलों में आधारभूत स्तर से प्रतिभा की खोज, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास तथा वैश्विक स्तर के खेल उपकरणों के निर्माण तक समग्र इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाकर देश को वैश्विक स्पोर्टिंग पावरहाउस बनाने के लिए कटिबद्ध है। देश में 'खेलो इंडिया', 'फिट इंडिया मूवमेंट' तथा खेल के व्यापक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के कारण युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह में वृद्धि हुई है।

उन्होंने आगे कहा कि खेलों में बढ़ती भागीदारी स्थानीय उत्पादन, इनोवेशन, स्टार्टअप्स और निर्यात (एक्सपोर्ट) के लिए बड़े अवसर सृजित कर रही है। उन्होंने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन अंतर्गत स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स विकसित करने तथा भविष्य में होने वाले अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों का लाभ उठाकर इस क्षेत्र के लिए समर्पित नीतिगत सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।

इस अवसर पर छोटाउदेपुर की प्रभारी मंत्री डॉ. मनीषाबेन वकील ने भी राज्य के सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास में खेल क्षेत्र के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर टेक्निकल सेशन में हेलो इंडिया के संयुक्त सचिव श्री विनिल कृष्णा तथा नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक श्री संजीत सिंह ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। छोटाउदेपुर की जिला कलेक्टर गार्गी जैन की अध्यक्षता में आयोजित पैनल डिस्कशन में केपीएमजी के पार्टनर प्रशांत शांतकुमारन, स्टैग इंटरनेशनल के अध्यक्ष श्री राकेश कोहली, शिव नरेश स्पोर्ट्स प्रा. लि. के एमडी एवं सीईओ श्री शिव प्रकाश सिंह, एगिलिटास के निदेशक श्री अजय कुमार पांडे, आनंदको स्पोर्टिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के आर एंड डी निदेशक श्री अर्जुन आनंद, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव श्री मोनल चौकसी तथा खेल विभाग के निदेशक के. एम. हरिलाल (आईटीएस) ने पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया। इस विचार-मंथन के दौरान उपयुक्त उत्पाद श्रेणियों की पहचान करने, आदिवासी युवाओं के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता के मॉडल तैयार करने, एमएसएमई को प्रोत्साहित करने, बाज़ार तक पहुंच को मजबूत बनाने, पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन पद्धतियां अपनाने तथा खेल उपकरण निर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए अनुकूल इकोसिस्टम विकसित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

'सुजलाम सुफलाम जल अभियान' के माध्यम से जल संग्रहण क्षमता में इस वर्ष 20,789 लाख घन फीट की वृद्धि : जल संसाधन राज्य मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल

▸▸ 'जल अभियान' के माध्यम से पिछले आठ वर्षों में जल संग्रहण क्षमता में कुल 1,38,039 लाख घन फीट की रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि

▸▸ चालू वर्ष में 13,315 कार्य पूर्ण, 2.30 लाख मानव दिवस का मिला रोजगार

▸▸ पिछले 8 वर्षों में जल संचयन के 1.23 लाख से अधिक कार्य संपन्न

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'कैच द रेन' अभियान अंतर्गत समग्र राज्य में पानी के संग्रहण का दायरा बढ़ाने तथा भूमिगत स्तर को ऊँचा लाने के उम्दा आशय के साथ चलाया जा रहा 'सुजलाम सुफलाम जल अभियान' जन भागीदारी के माध्यम से एक शानदार जन आंदोलन बन चुका है।

जल संसाधन एवं जलापूर्ति राज्य मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल ने बताया कि इस वर्ष 'सुजलाम सुफलाम जल अभियान' के माध्यम से जल संग्रहण क्षमता में 20,789 लाख घन फीट की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले 8 वर्षों में राज्य की जल संग्रहण क्षमता में रिकॉर्ड तोड़ कुल लगभग 1,38,039 लाख घन फीट की वृद्धि दर्ज हुई है। पानी बचाने और उसका व्यय रोकने के लिए जन मानस में जागरूकता आए; ऐसी दीर्घदृष्टि के साथ पिछले 08 वर्षों से यह अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि इस वर्ष मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से गत 23 फरवरी, 2026 को गांधीनगर से इस अभियान का राज्यव्यापी भव्य शुभारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में चालू वर्ष में समग्र राज्य में मई-2026 तक विभिन्न विभागों के समन्वय से कुल 13,315 कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए गए हैं।

इस अभियान अंतर्गत परंपरागत जल स्रोतों के नवीनीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिसमें चालू वर्ष में मुख्यतः तालाबों को गहरा करने के 2,450 कार्य, चेकडैम डिसिल्टिंग के 3,661 कार्य तथा चेकडैम रिपेयरिंग के 1,160 कार्य किए गए हैं। इसके अतिरिक्त; 626 किलोमीटर लंबाई में नहरों तथा 1,277 किलोमीटर लंबाई में नालों की साफ-सफाई की गई है। इन कार्यों के माध्यम से जल संग्रहण क्षमता में 20,789 लाख घन फीट की वृद्धि हुई है। इसके साथ श्रमिकों के लिए लगभग 2.30 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ है।

जल संसाधन राज्य मंत्री ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार के 6 प्रमुख विभाग जल संसाधन, जलापूर्ति विभाग, वन एवं पर्यावरण, शहरी विकास, ग्रामीण विकास विभाग और सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। इन कार्यों की मुख्यतः तीन पद्धतियाँ हैं; जिनमें जन भागीदारी, मनरेगा योजना और विभागीय रूप से कार्य पूर्ण किए जाते हैं।

उन्होंने इस अभियान की उपलब्धियाँ बताते हुए कहा कि दीर्घकालिक योजना तथा कड़े परिश्रम के परिणामस्वरूप पिछले 8 वर्षों में कुल 1,23,635 कार्य शुरू किए थे। इनमें से मुख्य रूप से तालाबों को गहरा करने एवं नए तालाबों के 39,770 कार्य, चेकडैम डिसिल्टिंग के 26,873 कार्य तथा चेकडैम रिपेयरिंग के 7,810 कार्य पूरे किए गए हैं। उन्होंने जोड़ा कि इसके अतिरिक्त; कुल 80,793 किलोमीटर लंबाई में नहरों तथा नालों की साफ-सफाई के कार्य शुरू किए गए थे, जिसके कारण जल संग्रहण क्षमता में कुल 1,38,039 लाख घन फीट की वृद्धि हुई है, जिसमें 206.73 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ है।

पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद - मंगलुरु साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ाई गई

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद एवं मंगलुरु के बीच स्पेशल किराए पर संचालित की जा रही साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की अवधि का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। अब यह ट्रेन 31 जुलाई 2026 तक अतिरिक्त फेरों के साथ संचालित की जाएगी, जिससे यात्रियों को यात्रा में अधिक सुविधा उपलब्ध होगी तथा अतिरिक्त यात्री यातायात का सुचारु प्रबंधन किया जा सकेगा।

ट्रेन संख्या 09424 अहमदाबाद – मंगलुरु साप्ताहिक स्पेशल (प्रत्येक शुक्रवार) [05 फेरे]

ट्रेन संख्या 09424 प्रत्येक शुक्रवार को 03 जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक अहमदाबाद से 16:00 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 21:00 बजे मंगलुरु जंक्शन पहुंचेगी।

प्रमुख ठहराव:

यह ट्रेन नडियाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, वसई रोड, भिवंडी रोड, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, खेड़, चिपलून, सावर्डा, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, सावंतवाड़ी रोड, थिविम, करमाली, मडगांव, काणकोण, कारवार, अंकोला, गोकर्ण रोड, कुमटा, मुर्डेश्वर, भटकल, मूकाम्बिका रोड बैंदूर, कुंदापुरा, उडुपी, मुल्की एवं सुरतकल स्टेशनों पर ठहरेगी।

कोच संरचना:

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे उपलब्ध रहेंगे।

बुकिंग जानकारी:

ट्रेन संख्या 09424 की बुकिंग 30 जून, 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से पूर्व ट्रेन के समय, ठहराव एवं अन्य विवरण की जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

मणिपुर में आर्थिक नाकाबंदी के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

मणिपुर, जो पिछले तीन वर्षों से देश में अशांति का कारण बना हुआ है, आज दो समुदायों के बीच शत्रुता के चलते और भी भड़क उठा है। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, जिसके चलते आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। मणिपुर के कुकी समुदाय बहुल कांग पोकपी जिले में लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध के कारण आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई है। 50 किलो चावल की बोरी की कीमत 1,400 रुपये से बढ़कर 1,700 रुपये और फिर 4,000 रुपये हो गई है। वहीं, कालाबाजारी में खाना पकाने के गैस सिलेंडर की कीमत 5,000 रुपये तक पहुंच गई है। पेट्रोल भी अब 250 रुपये से 280 रुपये प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। हाल ही में नागा समूहों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर विरोध प्रदर्शन और यातायात अवरोधन के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने छह अपहृत नागाओं की हत्या के लिए न्याय की मांग की थी। इन प्रतिबंधों के कारण पहाड़ी जिलों में ईंधन टैंकरों और खाद्य एवं अन्य आवश्यक सामग्री ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही काफी कम हो गई है। इनमें से कुछ ट्रकों को जला दिया गया है। आपूर्ति की कमी के कारण कई लोग खाना पकाने के लिए लकड़ी का उपयोग करने को मजबूर हैं। मणिपुर की आज यही स्थिति है!!!

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान इंडेक्स्ट बी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र प्रदान

दक्षिण गुजरात में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात समिट में केवल 11 ही दिनों में 350 कंपनियों को वाइब्रेंट में जोड़ने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र मुख्यमंत्री के करकमलों से प्रदान किया गया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान सोमवार को गुजरात सरकार के आधिकारिक निवेश प्रोत्साहन संस्थान इंडेक्स्ट-बी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र प्रदान किया।

इंडेक्स्ट-बी ने 'के एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड' के साथ मिलकर गत 2 मई, 2026 को सूरत में आयोजित बिजनेस एक्सपोजिशन में केवल 11 दिनों में ही सर्वाधिक कुल 350 प्रदर्शकों को जोड़ने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। इस उपलब्धि को मान्यता देते हुए इंडेक्स्ट-बी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से प्रदान किया गया।

उल्लेखनीय है कि इंडेक्स्ट-बी गुजरात सरकार के आधिकारिक निवेश प्रोत्साहन संस्थान के रूप में निवेशकों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉण्टैक्ट

के रूप में कार्य करता है। यह संस्थान निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मार्गदर्शन, आवश्यक सुविधाएँ तथा नीतिगत आधार प्रदान कर राज्य के औद्योगिक एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

इस अवसर पर उपस्थित महानुभावों ने इंडेक्स्ट-बी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए अभिनंदन दिया और राज्य के सर्वांगीण औद्योगिक विकास के लिए उसके कार्य की सराहना की।

भावनगर मंडल के चार कर्मचारी डीआरएम संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित, सतर्कता कर्तव्यनिष्ठा एवं त्वरित कार्रवाई से संभावित रेल दुर्घटनाएं टलीं

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में सुरक्षित रेल परिचालन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले चार कर्मचारियों को उनकी असाधारण सतर्कता, कर्तव्यनिष्ठा एवं त्वरित निर्णय क्षमता के लिए वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक श्री सी. आर. गरूडा की अनुशंसा पर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा द्वारा डीआरएम संरक्षा पुरस्कार (DRM Safety Award) से सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, भावनगर परा में आयोजित किया गया, जहां सभी सम्मानित कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र एवं मेडल प्रदान किए गए।

सम्मानित कर्मचारियों में श्री सुरेश डी. (कांटेवाला, जेतलसर), श्री सत्यजीत पांडेय (कांटेवाला, अलमपर), श्री जयेश वी. चौहान (प्वाइंट्समैन, वरतेज) तथा सुश्री हेमवर्षा एन. (पी. मैन, गोंडल) शामिल हैं। इन सभी कर्मचारियों ने ड्यूटी के दौरान अपनी सजगता एवं त्वरित कार्रवाई से संभावित रेल दुर्घटनाओं को टालते हुए सुरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक ने पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सराहना करते हुए उन्हें भावनगर मंडल के सभी रेल कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत बताया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कर्तव्यनिष्ठा, सतर्कता और सेवा के प्रति समर्पण ही सुरक्षित रेल परिचालन की सबसे मजबूत आधारशिला है।

श्री सुरेश डी. ने 27 मार्च 2026 को समपार फाटक संख्या 62/सी पर ड्यूटी के दौरान ट्रेन संख्या 59557 पोरबंदर–भावनगर के इंजन के नीचे गियर बॉक्स की भारी लोहे की पिन लटकती हुई देखी। उन्होंने तत्काल खतरे का हाथ संकेत देकर स्टेशन मास्टर को सूचना दी। त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित कर्मचारियों ने पिन को सुरक्षित रूप से बांधकर ट्रेन का संचालन सुरक्षित रूप से सुनिश्चित किया। उनकी सजगता से संभावित दुर्घटना टल गई।

श्री सत्यजीत पांडेय ने 11 मई 2026 को अलमपर स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान गुजर रही मालगाड़ी के 35वें वैगन में लटकता हुआ भाग देखा। उन्होंने तुरंत खतरे का संकेत देकर स्टेशन मास्टर को सूचित किया। समय रहते ट्रेन को रोककर दोष दूर किया गया और सुरक्षित रूप से आगे रवाना किया गया। उनकी सूझबूझ एवं तत्परता ने संभावित दुर्घटना को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री जयेश वी. चौहान ने 3/4 मई 2025 को ट्रैफिक फाटक संख्या 214/सी पर ड्यूटी के दौरान वरतेज स्टेशन की लाइन संख्या-3 पर रेल फ्रैक्चर (Rail Fracture) देखा। उन्होंने बिना विलंब स्टेशन मास्टर को सूचना दी, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों ने तत्काल मरम्मत कर संभावित गंभीर रेल दुर्घटना को टाल दिया। सुश्री हेमवर्षा एन. ने 13 जून 2026 को गोंडल स्थित समपार फाटक संख्या 48-बी पर ड्यूटी के दौरान एक मालगाड़ी के दो वैगनों में असामान्य स्पार्किंग देखी। उन्होंने तुरंत वीरपुर के डिप्टी स्टेशन मास्टर को सूचना दी। जांच में एक वैगन में ब्रेक बाइंडिंग तथा दूसरे में मेटल डिपॉजिट पाया गया। समय रहते दोष दूर कर ट्रेन को सुरक्षित रवाना किया गया। उनकी सतर्कता एवं कर्तव्यनिष्ठा ने संभावित दुर्घटना को टालने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने सभी सम्मानित कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि सुरक्षा के प्रति सजग और समर्पित कर्मचारी ही भारतीय रेल की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने सभी कर्मचारियों से भविष्य में भी इसी प्रकार सतर्कता, अनुशासन एवं उत्कृष्ट कार्य संस्कृति के साथ सुरक्षित रेल संचालन में अपना योगदान देने का आह्वान किया।

पश्चिम रेलवे का भावनगर मंडल अपने कर्मचारियों की सतर्कता, त्वरित निर्णय क्षमता एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यशैली की सराहना करता है। ऐसे समर्पित कर्मचारियों के प्रयास न केवल सुरक्षित रेल परिचालन को सुदृढ़ बनाते हैं, बल्कि यात्रियों, रेल संपत्ति एवं राष्ट्रीय संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा के साथ मंडल के सभी शाखाधिकारी उपस्थित थे।

वीजीआरसी मध्य गुजरात-वडोदरा

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मुंबई स्थित आयरलैंड के कॉन्सुल जनरल श्री पैट्रिक डफी के साथ फलदायी बैठक आयोजित की

▸▸ आयरलैंड के उद्योगों-निवेशकों को गुजरात के विशाल निवेश एवं व्यापार अवसरों का लाभ उठाने का आमंत्रण

▸▸ आयरलैंड के कॉन्सुल जनरल श्री पैट्रिक डफी ने आगामी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में सहभागी होने की उत्सुकता दर्शाई

▸▸ स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी तथा स्पोर्ट्स क्षेत्र में सहयोग को अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए परस्पर विचार-विमर्श

वडोदरा : वडोदरा में आयोजित हो रही मध्य गुजरात क्षेत्र की वीजीआरसी के दौरान सोमवार को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मुंबई स्थित आयरलैंड के कॉन्सुल जनरल श्री पैट्रिक डफी के साथ एक फलदायी बैठक आयोजित की।

इस बैठक में गुजरात-आयरलैंड के बीच आर्थिक भागीदारी को और मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने आगामी भारत-यूरोपीय संघ (इंडिया-ईयू) मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से नए अवसरों के जो द्वार खुले हैं, उसके संदर्भ में आयरलैंड के उद्योगों तथा निवेशकों को गुजरात में उपलब्ध विशाल निवेश एवं व्यापारिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रण दिया।

विशेष रूप से स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स क्षेत्र में सहयोग को अधिक प्रगाढ़ बनाने के विषय पर भी मुख्यमंत्री तथा कॉन्सुल जनरल ने चर्चाएँ कीं।

आयरलैंड के कॉन्सुल जनरल ने आगामी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट (वीजीजीआईएस)-2027 में सहभागी होने की उत्सुकता दर्शाई तथा परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के लिए कंट्री सेमिनार आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने वीजीजीआईएस-2027 में आने वाले आयरलैंड के प्रतिनिधिमंडल को पतंगोत्सव, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (एओयू) तथा अन्य उद्योगों की साइट विजिट कराने का सुझाव दिया।

इस बैठक में मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार दास, उद्योग विभाग की अपर मुख्य सचिव श्री ममता वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव श्री पी. भारती तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

आपातकाल की वर्षगांठ पर लोकतंत्र और मीडिया की स्वतंत्रता पर गंभीर बहस आयोजित की गई

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

1975 में आपातकाल की घोषणा की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर, पिछले मंगलवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में "लोकतंत्र के लिए खतरे और आगे की चुनौतियां" विषय पर एक चर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन देश के चार प्रमुख मानवाधिकार संगठनों - पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) दिल्ली, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (पीयूडीआर), सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी (सीएफडी) और जन खट्टक द्वारा किया गया था।

इस कार्यक्रम में कानूनी विशेषज्ञ, पत्रकार और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता आपातकाल से मिले सबक पर विचार-विमर्श करने और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने मौजूद समकालीन चुनौतियों का आकलन करने के लिए एक साथ आए। कारवां के संपादक थारुश बाल ने तर्क दिया कि आपातकाल को औपचारिक रूप से जन आंदोलनों और चुनावी हार के माध्यम से समाप्त किया गया था। आज भारतीय लोकतंत्र के सामने मौजूद चुनौतियाँ मौलिक रूप से भिन्न हैं। आपातकाल के दौरान, समाचार पत्रों पर खुलेआम सेंसरशिप लागू थी। आज, अधिकांश समकालीन मुख्यधारा के मीडिया औपचारिक सेंसरशिप के तहत काम करते हैं, क्योंकि उनका स्वामित्व सत्ताधारी प्रतिष्ठान की विचारधारा से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।

आज के दौर में मीडिया का स्वामित्व शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के हाथों में केंद्रित है। संपादक थारुश बाले ने तर्क दिया कि धनी औद्योगिक समूहों का ऐतिहासिक रूप से मीडिया पर काफी प्रभाव रहा है और दावा किया कि उनके समाचार पत्रों की राजनीतिक और वैचारिक विचारधारा अक्सर हिंदुत्व के अनुरूप रही है। उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक उदारीकरण ने समाचार संगठनों पर कॉरपोरेट प्रभाव को और मजबूत किया है। और विशेष रूप से स्वतंत्र डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनलों के उदय के साथ, लोग आज सच्चाई से अवगत हो रहे हैं। लेकिन इन चैनलों के पास निरंतर जमीनी रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन नहीं हैं। यह भी एक कड़वी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना होगा।